



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 987]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 26, 2016/वैशाख 6, 1938

No. 987]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 26, 2016/VAISAKHA 6, 1938

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

**का. आ. 1500 (अ).**—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 30.11.1994 की अधिसूचना संख्या का. आ. 878 (अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने क्रम संख्या 3 पर, "जानकीदेवी बजाज ग्राम विकास संस्था, मार्फत समाज सेवा केन्द्र, सर्वे संख्या 4272, अकुर्दी पोस्ट ऑफिस के पीछे, अकुर्दी, पुणे-411035" द्वारा "एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना" को कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना या योजना के रूप में अधिसूचित किया था; जिसे बाद में दिनांक 4.4.1995 की अधिसूचना संख्या का. आ. 293(अ) द्वारा कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 20.5.1998 की अधिसूचना संख्या का. आ. 438(अ) द्वारा कर-निर्धारण वर्ष 1999-2000 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 30.12.2002 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1384(अ) द्वारा कर-निर्धारण वर्ष 2002-03 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 5.7.2004 की अधिसूचना संख्या का. आ. 789(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-05 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 3.10.2008 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2400(अ) द्वारा इस अवधि के दौरान अतिरिक्त राशि इकट्ठा किए बिना धारा 35कग के तहत पहले से एकत्रित राशि खर्च करने के लिए आवेदक को समय देने हेतु वित्त वर्ष 2008-09 से प्रारंभ होने वाली दो वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; इस अवधि को 22.3.2010 की अधिसूचना संख्या का. आ. 644(अ) द्वारा वित्त वर्ष 2010-11 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में कार्य के क्षेत्र के विस्तार के लिए दिनांक 18.10.2011 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2410(अ) द्वारा संशोधित किया गया था; जिसे दिनांक 17.10.2013 की अधिसूचना संख्या का. आ. 3148(अ) द्वारा वित्त वर्ष 2015-16 से समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में मौजूदा क्षेत्रों अर्थात् महाराष्ट्र के पुणे, औरंगाबाद, वर्धा जिलों और राजस्थान के सीकर जिले के अलावा पूरे महाराष्ट्र में कार्य के क्षेत्र के विस्तार के लिए दिनांक 11.2.2015 की अधिसूचना संख्या का. आ. 473(अ) द्वारा संशोधित किया गया था

और जबकि दिनांक 20.5.1998 की अधिसूचना संख्या का. आ. 438(अ) द्वारा अनुमानित लागत को 118.00 लाख रुपए से बढ़ाकर 180.72 लाख रुपए कर दिया गया था; दिनांक 11.5.1999 की अधिसूचना संख्या सा. आ. 319(अ) द्वारा अनुमानित लागत को 182.72 लाख रुपए से और बढ़ाकर 298.60 लाख रुपए कर दिया गया था; दिनांक 5.7.2004 की अधिसूचना संख्या का. आ. 789(अ) द्वारा अनुमानित लागत को 298.60 लाख रुपए से और बढ़ाकर 704.14 लाख रुपए कर दिया गया था; दिनांक 14.10.2009 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2604(अ) द्वारा परियोजना लागत को 704.14 लाख रुपए से और बढ़ाकर 821.80 लाख रुपए कर दिया गया था; दिनांक 22.3.2010 की अधिसूचना संख्या का. आ. 644(अ) द्वारा अनुमानित लागत को 821.80 लाख रुपए से और बढ़ाकर 1219.80 लाख रुपए कर दिया गया था; परियोजना लागत को दिनांक 17.10.2013 की अधिसूचना संख्या का. आ. 3148(अ) द्वारा 1219.80 लाख रुपए से और बढ़ाकर 2021.80 लाख रुपए कर दिया गया और परियोजना लागत को दिनांक 11.2.2015 की अधिसूचना संख्या का. आ. 473(अ) द्वारा 2021.80 लाख रुपए से और बढ़ाकर 2971.80 लाख रुपए कर दिया गया।

और जबकि उक्त परियोजना या योजना का विस्तार 24 वर्षों से अधिक होने की संभावना है;

और जबकि परियोजना लागत 2971.80 लाख रुपए से बढ़कर 7971.80 लाख रुपए होने और कार्य के क्षेत्र का विस्तार भी भारत संघ के सभी राज्यों में होने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा योजना समुचित रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने उक्त परियोजना अथवा योजना को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को संशोधित करके 2971.80 लाख रुपए से 7971.80 लाख रुपए करने और कार्य के क्षेत्र का विस्तार भारत संघ के सभी राज्यों में करने के लिए आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत की सिफारिश की है। तथापि, धारा 35कग के तहत छूट, कंपनी अधिनियम की धारा 135 की अनुसूची VII और कंपनी (सीएसआर) नियमावली, 2014 के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी;

इसलिए, अब, केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निम्नलिखित आशय के लिए दिनांक 30.11.1992 की उक्त अधिसूचना संख्या का. आ. 878(अ) को संशोधित करती है, नामतः:-

(क) वित्त वर्ष 2016-17 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अतिरिक्त अवधि अर्थात् 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए उक्त परियोजना अथवा योजना का विस्तार करने के लिए;

(ख) उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 3 के सामने तालिका में, कॉलम (3) में परियोजना "एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना" के अंतर्गत कार्य के क्षेत्र में "भारत संघ के सभी राज्य" जोड़ा जाए और धारा 35कग के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाने वाली लागत की अधिकतम राशि से संबंधित कॉलम (4) में, "2971.80 लाख रुपए" अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के लिए "7971.80 लाख रुपए" अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ग) धारा 35कग के तहत छूट, कंपनी अधिनियम की धारा 135 की अनुसूची VII और कंपनी (सीएसआर) नियमावली, 2014 के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।

[सं. 17/2016/फा.सं.वी.27015/1/2016-एसओ(नैट.कॉम)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2016

**S.O.1500 (E).**— Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.878(E) dated the 30<sup>th</sup> November, 1992, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 3, "Integrated Rural Development Project" by "Jankidevi Bajaj Gram Vikas Sanstha, C/o Samaj Seva Kendra, Survey No.4272, Behind Akurdi Post Office, Akurdi, Pune – 411 035", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1993-1994; which was extended further vide notification number S.O.293(E) dated the 4<sup>th</sup> April, 1995 for a period of three years beginning with assessment year 1996-1997; which was extended further vide notification number S.O.438(E) dated the 20<sup>th</sup> May, 1998 for a period of three years beginning with

assessment year 1999-2000; which was extended further vide notification number S.O.1384(E) dated the 30th December, 2002 for a period of three years beginning with assessment year 2002-2003; which was extended further vide notification number S.O.789(E) dated the 5<sup>th</sup> July, 2004 for a period of three years beginning with financial year 2004-2005; which was extended further vide notification number S.O.2400(E) dated the 3<sup>rd</sup> October, 2008 for a period of two years beginning with financial year 2008-09 to give the applicant time to spend the already collected amount u/s. 35AC without raising further amount during the period; the period was further extended vide notification S.O. No 644(E) dated 22<sup>nd</sup> March, 2010 for further three years beginning with financial year 2010-11 and which was further amended vide notification number S.O.2410 (E) dated 18.10.2011 for expanding the area of work; which was further extended vide notification number S.O.3148(E) dated 17<sup>th</sup> October, 2013 for a further period of three years ending with financial year 2015-16 and which was further amended vide notification number S.O.473(E) dated 11th February, 2015 for expanding the area of work throughout Maharashtra in addition to existing area, i.e., Pune, Aurangabad, Wardha districts of Maharashtra and Sikar district of Rajasthan

And whereas by notification number S.O.438(E) dated the 20<sup>th</sup> May, 1998 the estimated cost was enhanced from Rs. 118.00 lakh to Rs.180.72 lakh; Vide notification number S.O.319(E) dated the 11<sup>th</sup> May, 1999 the estimated cost was further enhanced from Rs.182.72 lakh to Rs.298.60 lakh; vide notification number S.O.789(E) dated the 5<sup>th</sup> July, 2004 the estimated cost was further enhanced from Rs.298.60 lakh to Rs.704.14 lakh; vide notification number S.O.No.2604(E) dated 14.10.2009 the project cost was further enhanced from Rs. 704.14 lakh to Rs. 821.80 lakh, vide notification number S.O.644(E) dated 22<sup>nd</sup> March, 2010 the estimated cost was further enhanced from Rs. 821.80 lakh to Rs. 1219.80 lakhs, the project cost was further

enhanced from Rs. 1219.80 lakh to Rs.2021.80 lakh vide notification number S.O.3148(E) dated 17<sup>th</sup> October, 2013 and the project cost was further enhanced from Rs.2021.80 lakh to Rs. 2971.80 lakh vide notification number S.O. S.O.473(E) dated 11th February, 2015;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 24 years;

And whereas the project cost is likely to enhance from Rs.2971.80 lakh to Rs. 7971.80 lakh and also extension of area of work in all the states of Union of India;

And, whereas, the National Committee for the Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years and for amending the project cost from Rs. 2971.80 lakh to Rs. 7971.80 lakh and also extension of area of work in all the states of Union of India. However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby amends the said notification number S.O.878(E) dated the 30<sup>th</sup> November, 1992, to the following effect, namely :-

(a) For extending the said project or scheme for a further period of three years commencing with the financial year 2016-17 i.e. 2016-17, 2017-18 and 2018-19;

(b) In the said notification, in the Table against serial number 3, in column (3) the following may be added to the area of work under the project "Integrated Rural Development Project", "all the states of Union of India' and in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35AC, for the letters, figures and words "Rs. 2971.80 lakh", the letters, figures and words "Rs 7971.80 lakh" shall be substituted.

(c) The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No. 17/2016 / F.No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

**का. आ.1501 (अ).—**जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 11.10.2002 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1084(अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने क्रम संख्या 3 पर, "श्रीमती सविताबेन रमनलाल दह्यालाल शाह, सार्वजनिक हॉस्पिटल एवं प्रसूतिगृह ट्रस्ट, एटी और पीओ अम्बासन, तहसील और जिला मेहसाणा-384435, गुजरात" द्वारा "श्रीमती सविताबेन रमनलाल दह्यालाल शाह सार्वजनिक हॉस्पिटल, अम्बासन, जिला मेहसाणा, गुजरात" को वित्त वर्ष 2005-06 में समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 28.00 लाख रुपए की संग्रह राशि सहित 63.75 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना या योजना के रूप में चलाने के लिए

अधिसूचित किया था; जिसे बाद में दिनांक 5.7.2006 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1010(अ) द्वारा वित्त वर्ष 2007-08 में समाप्त होने वाली दो वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 17.6.2008 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1472(अ) द्वारा वित्त वर्ष 2010-11 में समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 27.4.2011 की अधिसूचना संख्या का. आ. 869(अ) द्वारा वित्त वर्ष 2013-14 में समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 31 जुलाई, 2014 की अधिसूचना संख्या सा. आ. 1970(अ) द्वारा वित्त वर्ष 2016-17 में समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 17.5.2010 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1147(अ) द्वारा, दिनांक 11.10.2002 की अधिसूचना संख्या सा. आ. 1084(अ) को संशोधित करके परियोजना लागत को 28.00 लाख रुपए की संग्रह राशि सहित 63.75 लाख रुपए से बढ़ाकर 28.00 लाख रुपए की एक संग्रह राशि सहित 113.75 लाख रुपए कर दिया गया था;

और जबकि परियोजना लागत 28.00 लाख रुपए की संग्रह राशि सहित 113.75 लाख रुपए से बढ़कर 28.00 लाख रुपए की एक संग्रह राशि सहित 163.75 लाख रुपए तक बढ़ने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा योजना समुचित रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने परियोजना लागत को 28.00 लाख रुपए की संग्रह राशि सहित 113.75 लाख रुपए से 28.00 लाख रुपए की एक संग्रह राशि सहित 163.75 लाख रुपए तक संशोधित करने के लिए आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत की सिफारिश की है। तथापि, धारा 35कग के तहत छूट, कंपनी अधिनियम की धारा 135 की अनुसूची VII और कंपनी (सीएसआर) नियमावली, 2014 के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी;

इसलिए, अब, केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, "श्रीमती सविताबेन रमनलाल दह्यालाल शाह सार्वजनिक हॉस्पिटल, अम्बासन, जिला मेहसाणा, गुजरात" जिसे "श्रीमती सविताबेन रमनलाल दह्यालाल शाह, सार्वजनिक हॉस्पिटल एवं प्रसूतिगृह ट्रस्ट, एटी और पीओ अम्बासन, तहसील और जिला मेहसाणा-384435, गुजरात" द्वारा चलाया जा रहा है, को अधिसूचित करती है और निम्नलिखित आशय के लिए दिनांक 11.10.2002 की उक्त अधिसूचना संख्या का.आ. 1084(अ) को संशोधित करती है, नामतः-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 3 के सामने तालिका में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35कग के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाने वाली लागत की अधिकतम राशि से संबंधित कॉलम (4) में, "28.00 लाख रुपए की संग्रह राशि सहित 113.75 लाख रुपए" अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के लिए "28.00 लाख रुपए की एक संग्रह राशि सहित 163.75 लाख रुपए" अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) धारा 35कग के तहत छूट, कंपनी अधिनियम की धारा 135 की अनुसूची VII और कंपनी (सीएसआर) नियमावली, 2014 के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।

[सं. 18/2016/फा.सं.वी.27015/1/2016-एसओ(नैट.कॉम)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2016

**S.O.1501(E).**—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1084(E) dated 11.10.2002 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 3, "Running of Smt. Savitaben Ramanlal Dahyalal Shah Sarvajanik Hospital, Ambasan, District Mehsana, Gujarat" by "Smt. Savitaben Ramanlal Dahyalal Shah, Sarvajanik Hospital & Prashutigrh Trust, AT & PO Ambasan, Tal. & District Mehsana -384435, Gujarat.", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.63.75 lakhs including a corpus fund of Rs.28.00 lakhs, for a period of three years ending with financial year 2005-06, which was further extended vide Notification number S.O. No.1010(E) dated 05.07.2006 for a further period of two years ending with financial year 2007-08, which was further extended vide S.O.1472(E) dated 17.06.2008 for a period of three years ending with financial year 2010-11, which was further extended vide Notification number 869(E) dated 27.4.2011 for a further period of three years ending with financial year 2013-14 and which was extended further vide notification number S.O. 1970(E) dated 31<sup>st</sup> July 2014 for a period of three years ending with financial year 2016-17;

And whereas vide notification number S.O. 1147(E) dated 17.5.2010, the project cost was enhanced from Rs.63.75 lakh including a corpus fund of Rs.28.00 lakh to Rs.113.75 lakh including a corpus fund of Rs.28 lakh, by amending notification number S.O.1084(E) dated 11.10.2002;

And whereas the project cost is likely to enhance from Rs.113.75 lakh including a corpus fund of Rs.28 lakh to Rs.163.75 lakh including a corpus of Rs. 28 lakh;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for amending the project cost from Rs.113.75 lakh including a corpus fund of Rs.28 lakh to Rs. 163.75 lakh including a corpus of Rs. 28 lakh. However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Running of Smt. Savitaben Ramanlal Dahyalal Shah Sarvajanik Hospital, Ambasan, District Mehsana, Gujarat", which is being carried out by "Smt. Savitaben Ramanlal Dahyalal Shah, Sarvajanik Hospital & Prashutighru Trust, AT & PO Ambasan, Tal. & District Mehsana -384435, Gujarat", further amends the said notification number S.O. 1084(E) dated 11.10.2002, to the following effect, namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 3, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section of 35AC of Income Tax Act, 1961 for the letters, figures and word "Rs.113.75 lakh including a corpus fund of Rs.28 lakh" the letters, figures and word "Rs. 163.75 lakh including a corpus of Rs. 28 lakh" shall be substituted.

(b). The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No. 18/2016 / F.No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

**का. आ.1502 (अ).**—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 21.07.2014 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1872(अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने क्रम संख्या 14 पर, "एशियन सोसाइटी ऑफ कॉन्टिन्यूयिंग मेडिकल एजुकेशन, सारिका मैसन न. 2, लेक एरिया फर्स्ट स्ट्रीट, तुंगाम्बक्कम, चेन्नई-600034, तमिलनाडु" द्वारा "एशियन सोसाइटी ऑफ कॉन्टिन्यूयिंग मेडिकल एजुकेशन" को वित्त वर्ष 2016-17 में समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 31.07 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना या योजना के रूप में अधिसूचित किया था;

और जबकि परियोजना लागत 31.07 करोड़ रुपए से बढ़कर 67.49 करोड़ रुपए तक बढ़ने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा योजना समुचित रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने परियोजना लागत को 31.07 करोड़ रुपए से 67.49 करोड़ तक संशोधित करने के लिए आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत की सिफारिश की है। तथापि, धारा 35कग के तहत छूट, कंपनी अधिनियम की धारा 135 की अनुसूची VII और कंपनी (सीएसआर) नियमावली, 2014 के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी;

इसलिए, अब, केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (क) निम्नलिखित आशय के लिए दिनांक 21.07.2014 की उक्त अधिसूचना संख्या का. आ. 1872(अ) को संशोधित करती है, नामतः:-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 14 के सामने तालिका में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35कग के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाने वाली लागत की अधिकतम राशि से संबंधित कॉलम (4) में, "31.07 करोड़ रुपए" अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के लिए "67.49 करोड़ रुपए" अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) धारा 35कग के तहत छूट, कंपनी अधिनियम की धारा 135 की अनुसूची VII और कंपनी (सीएसआर) नियमावली, 2014 के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।

[सं. 19/2016/फा.सं.वी.27015/1/2016-एसओ(नैट.कॉम)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2016

**S.O.1502(E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1872(E) dated 21.07.2014 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 14, “Asian Society of Continuing Medical Education ” by “Asian Society of Continuing Medical Education, Sharika Mansion No.2, Lake Area First Street, Nungambakkam, Chennai – 600 034 - Tamil Nadu”, as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 31.07 crore for a period of three years ending with financial year 2016-17;

And whereas the project cost is likely to enhance from Rs.31.07 crore to Rs. 67.49 crore;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for amending the project cost from Rs.31.07 crore to Rs. 67.49 crore. However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (a) further amends the said notification number S.O. 1872(E) dated 21.07.2014, to the following effect, namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 14, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section of 35AC of Income Tax Act, 1961 for the letters, figures and word “Rs.31.07 crore” the letters, figures and word “Rs. 67.49 crore” shall be substituted.

(b). The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No. 19/2016 / F.No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

**का. आ.1503 (अ).**—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 23.10.2010 की अधिसूचना संख्या का. आ. 3021(अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने क्रम संख्या 23 पर, “चिंगटॉन डेवलपमेंट सोसाइटी, फैबंग खुल्लेन, पो.आ. सेनापति, सेनापति जिला, मणिपुर-795106” द्वारा “आय सृजन के माध्यम से गरीब जनजातियों की आर्थिक सशक्तीकरण” को वित्त वर्ष 2012-13 में समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 484.50 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना या योजना के रूप में अधिसूचित किया था और जिसे दिनांक 31.07.2014 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1951(अ) द्वारा वित्त वर्ष 2015-16 में समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 31.07.2014 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1951(अ) द्वारा परियोजना लागत को 484.50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1007.50 लाख रुपए कर दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या योजना का विस्तार 6 वर्षों से अधिक होने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा योजना समुचित रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने उक्त परियोजना या योजना को तीन वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने हेतु आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत की सिफारिश की

है। तथापि, धारा 35कग के तहत छूट, कंपनी अधिनियम की धारा 135 की अनुसूची VII और कंपनी (सीएसआर) नियमावली, 2014 के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी;

इसलिए, अब, केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, 1007.50 लाख रुपए की स्वीकृत लागत में कोई परिवर्तन किए बिना i) "आय सृजन के माध्यम से गरीब जनजातियों की आर्थिक सशक्तीकरण" योजना या परियोजना, जिसे "चिंगटॉन डेवलपमेंट सोसाइटी, फैबंग खुल्लेन, पो.आ. सेनापति, सेनापति जिला, मणिपुर-795106" द्वारा चलाया जा रहा है, को वित्त वर्ष 2016-17 से आरंभ होने वाली तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि अर्थात् 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए एक पात्र परियोजना या योजना के रूप में अधिसूचित करती है;

(ख) धारा 35कग के तहत छूट, कंपनी अधिनियम की धारा 135 की अनुसूची VII और कंपनी (सीएसआर) नियमावली, 2014 के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।

[सं. 20/2016/फा.सं.वी.27015/1/2016-एसओ(नैट.कॉम)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2016

**S.O.1503(E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 3021(E) dated 23.10.2010 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 23, "Economic Empowerment of Tribal poor through Income Generation Programme" by "Chington Development Society, Phaibung Khullen, P.O. Senapati, Senapati District, Manipur-795106", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.484.50 lakh, for a period of three years ending with financial year 2012-13 and which was further extended vide S.O. No. 1951(E) dated 31.07.2014 for a period of three years ending with financial year 2015-16;

And whereas by notification number S.O. 1951(E) dated 31.07.2014 the estimated cost was enhanced from Rs. 484.50 lakh to Rs.1007.50 lakh;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 6 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, for specifying the said project or scheme for a further period of three years. However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby a) notifies the scheme or project "Economic Empowerment of Tribal poor through Income Generation Programme", which is being carried out by "Chington Development Society, Phaibung Khullen, P.O. Senapati, Senapati District, Manipur-795106", without any change in the approved cost of Rs. 1007.50 lakh, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with the financial year 2016-17 i.e. 2016-17, 2017-18 and 2018-19;

(b). The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No.20/2016 / F.No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

**का. आ.1504 (अ).**—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 18.12.2013 की अधिसूचना संख्या का. आ. 3696(अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने क्रम संख्या 2 पर, "थिरुमलाई चैरिटी ट्रस्ट 'थिरुमलाई' 103 सेवरीवडाला मुम्बई-400031" द्वारा "प्राथमिक और

द्वितीयक स्वास्थ्य सेवा के लिए एकीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य और विकास कार्यक्रम" को वित्त वर्ष 2015-16 में समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 962.75 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना या योजना के रूप में अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या योजना का विस्तार 3 वर्षों से अधिक होने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा योजना समुचित रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने उक्त परियोजना या योजना को तीन वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने हेतु आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत की सिफारिश की है। तथापि, धारा 35कग के तहत छूट, कंपनी अधिनियम की धारा 135 की अनुसूची VII और कंपनी (सीएसआर) नियमावली, 2014 के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी;

इसलिए, अब, केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, 962.75 लाख रुपए की स्वीकृत लागत में कोई परिवर्तन किए बिना "प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य सेवा के लिए एकीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य और विकास कार्यक्रम" योजना या परियोजना, जिसे "थिरुमलाई चैरिटी ट्रस्ट 'थिरुमलाई' 103 सेवरीवडाला मुम्बई-400031" द्वारा चलाया जा रहा है, को वित्त वर्ष 2016-17 से आरंभ होने वाली तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि अर्थात् 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए एक पात्र परियोजना या योजना के रूप में अधिसूचित करती है;

(ख) धारा 35कग के तहत छूट, कंपनी अधिनियम की धारा 135 की अनुसूची VII और कंपनी (सीएसआर) नियमावली, 2014 के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।

[सं. 21/2016/फा.सं.वी.27015/1/2016-एसओ(नैट.कॉम)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2016

**S.O.1504(E).**—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 3696(E) dated 18.12.2013 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 2, "Integrated Community Health and Development Programme for Primary and Secondary Healthcare" by "Thirumalai Charity Trust 'Thirumalai' 103 Sewreewadala Mumbai- 400031.", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 962.75 lakh for a period of three years ending with financial year 2015-16;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years. However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Integrated Community Health and Development Programme for Primary and Secondary Healthcare", which is being carried out by "Thirumalai Charity Trust 'Thirumalai' 103 Sewreewadala Mumbai- 400031", as an eligible project or scheme for a further period of three years, without any change in the approved cost of Rs. 962.75 lakh commencing with the financial year 2016-17 i.e. 2016-17, 2017-18 and 2018-19;

(b). The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No.21/2016 / F.No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)



**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

**का. आ.1505(अ).-** जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 10.03.1997 की अधिसूचना सं. का. आ. 180 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "कैंसर रोगी सहायता संघ, 5, मल्होत्रा हाउस, फोर्ट, मुम्बई- 400001" द्वारा " (क) मुम्बई, महाराष्ट्र में कैंसर का पता लगाने संबंधी इकाई के लिए निर्माण उपस्करों का नवीकरण और साज सज्जा; और (ख) अहमदनगर, नांदेड, बुलदाना, परभानी, अकोला अमरावती, यवतमाल, जलगांव, धुले, बीड और मुम्बई, महाराष्ट्र में कैंसर संबंधी जागरूकता शिक्षा और इसका पता लगाने संबंधी कैम्पों" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1997-98 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 6 पर अधिसूचित किया था; जिसे बाद में दिनांक 5.07.2000 की अधिसूचना सं. का. आ. 638 (अ) के द्वारा निर्धारण वर्ष 2000-01 को प्रारंभ होने वाले तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 09.01.2002 की अधिसूचना सं. का. आ. 1280 (अ) के द्वारा निर्धारण वर्ष 2003-04 को प्रारंभ होने वाले तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 03.02.2006 की अधिसूचना सं. का. आ. 148 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-06 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 21.01.2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 246(अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 18.10.2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 2400 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 11.02.2015 की अधिसूचना सं. का. आ. 479 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि परियोजना लागत के 365.67 लाख रुपये से बढ़कर 700.00 लाख रुपये होने की सम्भावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना लागत को 365.67 लाख रुपये संशोधित करके 700.00 लाख रुपये करने की सिफारिश की है। तथापि, धारा 35 क ग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा (क) 10.03.1997 की उक्त अधिसूचना सं. का. आ. 180 (अ) को निम्नलिखित आशय से संशोधित करती है, नामतः :-

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 6 के सामने तालिका में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35कग के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाने वाली लागत की अधिकतम राशि से संबंधित कालम (4) में "365.67 लाख रुपये" अक्षरों, अंकों और शब्दों को "700.00 लाख रुपये" अक्षरों, अंकों और शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) धारा 35 क ग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।

[सं. 22/2016 /फा. सं. वी.27015/1/2016-एस ओ( एन. सी.)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th April, 2016

**S.O.1505 (E).—** Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.180(E) dated the 10<sup>th</sup> March, 1997, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 6, "(a) Renovation of building equipments and furnishing of Cancer Detection Unit at Mumbai Maharashtra; and (b) Cancer Awareness, Education and Detection camps; at Ahmednagar, Nanded, Buldana, Parbhani, Akola Amravati,

Yavatmal, Jalgoan, Dhule, Beed and Mumbai, Maharashtra” by “Cancer Patients Aid Association, 5, Malhotra House, Fort, Mumbai – 400001”, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1997-1998; which was extended further vide notification number S.O.638(E) dated the 5<sup>th</sup> July, 2000 for a period of three years beginning with assessment year 2000-2001; which was extended further vide notification number S.O.1280(E) dated the 9<sup>th</sup> January, 2002 for a period of three years beginning with assessment year 2003-2004; which was extended further vide notification number S.O.148(E) dated the 3<sup>rd</sup> February, 2006 for a period of three years beginning with financial year 2005-2006; which was extended further vide notification number S.O.246(E) dated the 21<sup>st</sup> January, 2009 for a period of three years beginning with financial year 2008-09, which was further extended vide notification number 2400(E) dated 18.10.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14 and which was further extended vide notification number 479(E) dated 11.2.2015 for a period of three years ending with financial year 2016-17 ;

And whereas the project cost is likely to enhance from Rs.365.67 lakh to Rs. 700.00 lakh;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for amending the project cost from Rs.365.67 lakh to Rs. 700.00 lakh. However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (a) further amends the said notification number S.O. 180(E) dated the 10<sup>th</sup> March, 1997, to the following effect, namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 6, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section of 35AC of Income Tax Act, 1961 for the letters, figures and word “Rs. 365.67 lakh” the letters, figures and word “Rs. 700.00 lakh” shall be substituted.

(b). The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No. 22 /2016 / F.No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

**का. आ.1506 (अ).-** जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 12.07. 2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 1649(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “स्माईल फाउंडेशन, वी-11, प्रथम स्तर, ग्रीन पार्क, एक्सटेंशन, दिल्ली- 110016” द्वारा “मिशन एजूकेशन, दिल्ली” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 1.82 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 04 पर अधिसूचित किया था और जिसे बाद में दिनांक 17.10.2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 3143 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम को छह वर्षों से आगे बढ़ने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है। तथापि, धारा 35 क ग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (क) एतद्वारा “स्माईल फाउंडेशन, वी-11, प्रथम स्तर, ग्रीन पार्क, एक्सटेंशन, दिल्ली- 110016” द्वारा चलाई जा रही “मिशन एजूकेशन, दिल्ली” की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2016-17 से

प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए 1.82 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

(ख) धारा 35 कग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।

[सं. 23/2016 /फा. सं. वी.27015/1/2016 एस ओ( एन. सी.)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2016

**S.O. 1506 (E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1649 (E) dated 12<sup>th</sup> July, 2010 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 4 “Mission Education, Delhi” by “Smile Foundation,, V-11, Ist Level, Green Park Extension, Delhi - 110016”, as an eligible project at the estimated cost of Rs.1.82 crore for a period of three years ending with financial year 2012-13 and which was further extended vide S.O. No. 3143(E) dated 17.10.2013 for a period of three years ending with financial year 2015-16;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 6 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years; However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961),- (a) hereby notifies the scheme or project “Mission Education, Delhi” which is being carried out by “Smile Foundation,, V-11, Ist Level, Green Park Extension, Delhi- 110016”, without any change in the approved cost of Rs.1.82 crore, as an eligible project or scheme, for a further period of three years commencing with the financial year 2016-17 i.e. 2016-17, 2017-18 and 2018-19;

(b). The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No. 23/2016 / F.No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

**का. आ.1507 (अ).**- जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 29.03.2007 की अधिसूचना सं. का. आ. 466 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “श्री सत्य साईं सेन्ट्रल ट्रस्ट, प्रशांति, निलायम- 515134, अनंतपुर जिला आंध्र प्रदेश” द्वारा “प्रशांतिग्राम (आंध्र प्रदेश) में श्री सत्य साईं उच्चतर चिकित्सा विज्ञान संस्थान का संचालन और रख-रखाव, व्हाईटफील्ड, बेंगलुरु (कर्नाटक) में श्री सत्य साईं उच्चतर चिकित्सा विज्ञान संस्थान का संचालन और रख-रखाव, श्री सत्य साईं चलता- फिरता अस्पताल का संचालन, न्यास के लिए कार्पस निधि का निर्माण” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2009-10 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 100 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 193.20 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 21 पर अधिसूचित किया था; जिसे बाद में दिनांक 17.05.2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 1148 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाले तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 11.10.2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 2528 (अ) के द्वारा आगे संशोधित किया गया था कि 30.11.2010 की स्थिति के अनुसार इसकी मौजूदा परिसंपत्तियों और देयताओं के साथ अनुमोदित परियोजना को “श्री सत्य साईं सेन्ट्रल ट्रस्ट” को हस्तांतरित किए जाने की अनुमति दी जाती है और जिसे बाद में दिनांक 17.10.2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 3142 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 17.10.2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 3142 (अ) के द्वारा अनुमानित लागत को 100 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 193.20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 596.20 करोड़ रुपये कर दिया गया था।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि परियोजना लागत को 100 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 596.20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 936.20 करोड़ रुपये करने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को 100 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 596.20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 936.20 करोड़ रुपये करने की सिफारिश की है। तथापि, धारा 35 कग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (क) एतद्वारा “श्री सत्य साईं सेन्ट्रल ट्रस्ट, प्रशांति, निलायम- 515134, अनंतपुर जिला आंध्र प्रदेश” द्वारा चलाई जा रही “प्रशांतिग्राम (आंध्र प्रदेश) में श्री सत्य साईं उच्चतर चिकित्सा विज्ञान संस्थान का संचालन और रख-रखाव, ब्हाईटफील्ड, बेंगलुरु (कर्नाटक) में श्री सत्य साईं उच्चतर चिकित्सा विज्ञान संस्थान का संचालन और रख-रखाव, श्री सत्य साईं चलता- फिरता अस्पताल का संचालन, न्यास के लिए कार्पस निधि का निर्माण” की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए अधिसूचित करती है;

(ख) दिनांक 29.03.2007 की उक्त अधिसूचना सं. का. आ. 466 (अ) को निम्नलिखित आशय से संशोधित करती है, नामतः -

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 21 के सामने तालिका में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35कग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली लागत की अधिकतम राशि से संबंधित कालम (4) में “100 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 596.20 करोड़ रुपये” से संबंधित अक्षरों, अंकों और शब्दों को “150 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 936.20 करोड़ रुपये” से संबंधित अक्षरों, अंकों और शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ग) धारा 35 कग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।

[सं. 24/2016 /फा. सं. वी -27015/1/2016 एस ओ( एन. सी)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2016

**S.O.1507 (E).—** Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 466(E) dated 29<sup>th</sup> March, 2007 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 21 “Running and maintenance of Sri Sathya Sai Institute of Higher Medical Sciences at Prasanthigram (Andhra Pradesh), running and maintenance of Sri Sathya Sai Institute of Higher Medical Sciences at Whitefield, Bangalore (Karnataka), running and maintenance of Sri Sathya Sai Mobile Hospital, building a corpus fund for the Trust” by “Sri Sathya Sai Central Trust, Prashanthi Nilayam-515134, Anantapur Dist, Andhra Pradesh”, as an eligible project at the estimated cost of Rs.193.20 crore including a corpus fund of Rs.100 crore for a period of three years ending with financial year 2009-10; which was further extended vide notification number S.O.1148(E) dated 17<sup>th</sup> May, 2010 for a period of three more years ending with financial year 2012-13; which was further amended vide notification number S.O. 2528(E) dated 11<sup>th</sup> October, 2010 that the approved project is allowed to be transferred with its existing assets and liabilities as on 30.11.2010 to “Sri Sathya Sai Central Trust” and which was further extended vide notification number S.O. 3142(E) dated the 17<sup>th</sup> October, 2013 for a period of three more years ending with financial year 2015-16;

And whereas by notification number S.O. 3142(E) dated the 17<sup>th</sup> October, 2013 the estimated cost was enhanced from Rs. Rs. 193.20 crore including a Corpus fund of Rs.100 crore to Rs. 596.20 crore including a Corpus fund of Rs.100 crore.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 9 years;

And whereas the project cost is likely to enhance from Rs. 596.20 crore including a Corpus fund of Rs.100 crore to Rs. 936.20 crore including a Corpus fund of Rs.150 crore;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years and for amending the project cost from Rs. 596.20 crore including a Corpus fund of Rs.100 crore to Rs. 936.20 crore including a Corpus fund of Rs.150 crore. However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961),- (a) hereby notifies the scheme or project "Running and maintenance of Sri Sathya Sai Institute of Higher Medical Sciences at Prasanthigram (Andhra Pradesh), running and maintenance of Sri Sathya Sai Institute of Higher Medical Sciences at Whitefield, Bangalore (Karnataka), running and maintenance of Sri Sathya Sai Mobile Hospital, building a corpus fund for the Trust" which is being carried out by "Sri Sathya Sai Central Trust, Prashanthi Nilayam-515134, Anantapur Dist, Andhra Pradesh", as an eligible project or scheme, for a further period of three years commencing with financial year 2016-17 i.e. 2016-17, 2017-18 and 2018-19;

(b) further amends the said notification number S.O.466 (E) dated 29.3.2007, to the following effect, namely :-

In the said notification, in the Table against serial number 21 in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC of Income Tax Act, 1961, for the letters, figures and words "Rs. 596.20 crore including a Corpus fund of Rs.100 crore", the letters, figures and words "Rs. 936.20 crore including a Corpus fund of Rs.150 crore" shall be substituted.

(c). The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No.24/2016 / F.No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

**का. आ.1508 (अ).**- जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 29.03.2007 की अधिसूचना सं. का. आ. 466 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "साधु वासवानी मिशन, 10, साधु वासवानी पथ, महाराष्ट्र, 411001" द्वारा "नेत्रहीनों के लिए नेत्र दृष्टि और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2007-08 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 5 पर अधिसूचित किया था; जिसे बाद में दिनांक 17.05.2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 141 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 17.10.2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 3174 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है। तथापि, धारा 35 क ग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (क) एतद्वारा "साधु वासवानी मिशन, 10, साधु वासवानी पथ, महाराष्ट्र, 411001" द्वारा चलाई जा रही "नेत्रहीनों के लिए नेत्र दृष्टि और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल" की परियोजना अथवा स्कीम को

वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए 62.82 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है;

(ख) धारा 35 कग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।

[सं. 25/2016 /फा. सं. वी -27015/1/2016 एस ओ( एन. सी)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2016

**S.O.1508 (E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O. 466(E) dated 29th March, 2007, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 5, for “Sight for the sightless & Quality Healthcare” by “Sadhu Vaswani Mission, 10, Sadhu Vaswani Path, Maharashtra – 411001”, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2007-08; which was vide notification number S.O. 141(E) dated 17.05.2010 extended for a period of three years ending with financial year 2012-13 which was vide notification number S.O. 3174(E) dated 17.10.2013 extended for a period of three years ending with financial year 2015-16.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond nine years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years. However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (a) hereby specifies the scheme or project for “Sight for the sightless & Quality Healthcare” which is being carried out by “Sadhu Vaswani Mission, 10, Sadhu Vaswani Path, Maharashtra – 411001”, without any change in the approved cost of Rs. 62.82 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial year 2016-17 i.e. 2016-17, 2017-18 and 2018-19;

(b). The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No.25/2016 / F.No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

**का. आ.1509 (अ).**— जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 16.07.2007 की अधिसूचना सं. का. आ. 1145 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “सेवालय, कासुवा गांव, डाकघर पक्कम समीप तिरुनिनरावुर, 602024-तमिलनाडु” द्वारा “सेवालय स्कूल के संचालन व्यय को पूरा करने और कॉर्पस निधि के निर्माण के लिए सेवालय स्कूल व्यय परियोजना” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2007-08 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 03 पर अधिसूचित किया था; जिसे बाद में दिनांक 22.03.2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 638 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 27.12.2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 3847 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि परियोजना लागत को 3.00 करोड़ रुपये की कॉर्पस निधि सहित 4.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3.00 करोड़ रुपये की कॉर्पस निधि सहित 10.00 करोड़ रुपये करने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने और परियोजना लागत को 3.00 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 4.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3.00 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 10.00 करोड़ रुपये करने की सिफारिश की है। तथापि, धारा 35 कग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (क) एतद्वारा "सेवालय, कासुवा गांव, डाकघर पक्कम समीप तिरुनिरावुर, 602024-तमिलनाडु" द्वारा चलाई जा रही "सेवालय स्कूल के संचालन व्यय को पूरा करने और कॉर्पस निधि के निर्माण के लिए सेवालय स्कूल व्यय परियोजना" की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए अधिसूचित करती है;

(ख) दिनांक 16.07.2007 की उक्त अधिसूचना सं. का. आ. 1145 (अ) को निम्नलिखित आशय से संशोधित करती है, नामतः

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं० 3 के सामने तालिका में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35कग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली लागत की अधिकतम राशि से संबंधित कालम (4) में "3.00 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 4.00 करोड़ रुपये" से संबंधित अक्षरों, अंकों और शब्दों को "3.00 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 10.00 करोड़ रुपये" से संबंधित अक्षरों, अंकों और शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ग) धारा 35 कग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।

[सं. 26/2016 /फा. सं. वी -27015/1/2016 एस ओ( एन. सी)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2016

**S.O.1509 (E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1145(E) dated the 16<sup>th</sup> July, 2007, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 3, "Sevalaya School expenses project to meet the running expenses of the school and to build corpus fund" by "Sevalaya, Kasuva Village, Pakkam PO near Thiruninravur, 602024, Tamil Nadu", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2007-08; which was further extended vide notification S.O. No.638(E) dated 22.03.2010 for a period of three years ending with financial year 2012-13 and which was further extended vide notification S.O. No. 3847(E) dated 27.12.2013 for a period of three years ending with financial year 2015-16;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond nine years;

And whereas the project cost is likely to enhance from Rs.4.00 crore including a corpus fund of Rs.3.00 crore to Rs. 10.00 crore including a corpus fund of Rs.3.00 crore;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years and for amending the project cost from Rs. 4.00 crore including a corpus fund of Rs.3.00 crore to Rs. 10.00 crore including a corpus fund of Rs.3.00 crore. However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (a) hereby notifies the scheme or project "Sevalaya School expenses project to meet the running expenses of the school and to build corpus fund" by "Sevalaya, Kasuva Village, Pakkam PO near Thiruninravur, 602024, Tamil Nadu", for a further period of three years beginning with the financial year 2016-17 i.e. 2016-17, 2017-18 and 2018-19 ;

(b) further amends the said notification number S.O. 1145(E) dated the 16<sup>th</sup> July, 2007, to the following effect, namely :-

In the said notification, in the Table against serial number 3 in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC of Income Tax Act, 1961, for the letters, figures and words “Rs.4.00 crore including a corpus fund of Rs.3.00 crore”, the letters, figures and words “Rs. 10.00 crore including a corpus fund of Rs.3.00 crore” shall be substituted.

(c). The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No.26 /2016 / F.No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA,Dy. Secy. (National Committee)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल 2016

**का. आ.1510 (अ).**— जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 11 मई 2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 1052 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम, स्वामी विवेकानंद मार्ग, डाकघर वृन्दावन, जिला मथुरा, उ.प्र.- 281121” द्वारा “अवसंरचना विकास और कार्पस निधि ” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2010-11 को प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 14 पर अधिसूचित किया था और जिसे दिनांक 12.03.2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 641 (अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक बढ़ाने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है। तथापि, धारा 35 क ग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (क) एतद्वारा “रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम, स्वामी विवेकानंद मार्ग, डाकघर वृन्दावन, जिला मथुरा, उ.प्र.- 281121” द्वारा चलाई जा रही “अवसंरचना विकास और कार्पस निधि” की परियोजना अथवा स्कीम को 10 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 34.15 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि अर्थात्, 2016-17, 2017-2018 और 2018-19 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

(ख) धारा 35 क ग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।

[सं. 27/2016 /फा. सं. वी -27015/1/2016 एस ओ( एन. सी)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2016

**S.O.1510 (E).**— Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.1052 (E) dated 11<sup>th</sup> May, 2010, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 14, “Infrastructure development & corpus fund” by “the Ramakrishna Mission Sevashrama, Swami Vivekananda Marg, PO Vrindaban, District Mathura, Uttar Pradesh-281121”, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2010-11 and which was further extended vide notification S.O. No. 641(E) dated 12.3.2013 for a period of three years ending with financial year 2015-16;



And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years. However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (a) hereby notifies the scheme or project "Infrastructure development & corpus fund" which is being carried out by "the Ramakrishna Mission Sevashrama, Swami Vivekananda Marg, PO Vrindaban, District Mathura, Uttar Pradesh-281121", without any change in the approved cost of Rs. 34.15 crore including a corpus fund of 10 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with the financial year 2016-17 i.e. 2016-17, 2017-18 and 2018-19;

(b). The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No.27 /2016 / F.No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

**का. आ.1511 (अ).-** जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 2 फरवरी 1996 की अधिसूचना संख्या सा. आ. 92 (अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने पर, "करूणा न्यास, 22, गौतम नगर, नारणपुरा रेलवे क्रासिंग के समीप, अहमदाबाद- 13" द्वारा "सम्पूर्ण गुजरात में नेत्र आपरेशन, पोलियो आपरेशन शिविरों का संचालन, ऑक्सीजन सिलेंडर सेवा और रोगी वाहन सेवा" को कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना या योजना के रूप में क्रम संख्या 5 पर अधिसूचित किया था; जिसे बाद में दिनांक 16.01.1998 की अधिसूचना सं. का. आ. 57 (अ) द्वारा कर-निर्धारण वर्ष 1999-2000 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 20.06.2001 की अधिसूचना सं. का. आ. 539 (अ) द्वारा कर-निर्धारण वर्ष 2002-03 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 2.02.2005 की अधिसूचना सं. का. आ. 143 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-05 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 04.06.2008 की अधिसूचना संख्या सा. आ. 1307 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 27.12.2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 3861(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 20.06.2001 की अधिसूचना सं. का. आ. 539 (अ) द्वारा अनुमानित लागत को 94.00 लाख रुपए से बढ़ाकर 128.00 लाख रुपए कर दिया गया था; दिनांक 04.06.2008 की अधिसूचना सं. का. आ. 1307 (अ) द्वारा अनुमानित लागत को 128.00 लाख रुपए से और बढ़ाकर 153.00 लाख रुपए कर दिया गया था और जबकि दिनांक 27.12.2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 3861 (अ) द्वारा अनुमानित लागत को 153 लाख रुपए से और बढ़ाकर 200 लाख रुपए कर दिया गया था और जबकि दिनांक 11.02.2015 की अधिसूचना सं. का. आ. 472 (अ) द्वारा अनुमानित लागत को 200 लाख रुपए से बढ़ाकर 270 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 470 लाख रुपये कर दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या योजना के 18 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि परियोजना लागत 270 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 470 लाख रुपये से बढ़ाकर 270 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 500 लाख रुपये करने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा योजना समुचित रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने उक्त परियोजना अथवा योजना को आयकर

नियमावली, 1962 के नियम 11ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने और परियोजना लागत को 270 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 470 लाख रुपये से बढ़ाकर 270 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 500 लाख रुपये करने की सिफारिश की है। तथापि, धारा 35कग के तहत छूट, कंपनी अधिनियम की धारा 135 की अनुसूची VII और कंपनी (सीएसआर) नियमावली, 2014 के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी;

इसलिए, अब, केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (क) एतद्वारा, "करूणा न्यास, 22, गौतम नगर, नारणपुरा रेलवे क्रॉसिंग के समीप, अहमदाबाद- 13" द्वारा चलाई जा रही "सम्पूर्ण गुजरात में नेत्र आपरेशन, पोलियो आपरेशन शिविरों का संचालन, ऑक्सीजन सिलेंडर सेवा और रोगी वाहन सेवा" परियोजना या स्कीम को वित्त वर्ष 2016-17 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए अधिसूचित करती है;

(ख) 2.02.1996 की उक्त अधिसूचना सं. का. आ. 92 (अ) को निम्नलिखित आशय से संशोधित करती है, नामत :-

‘उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 5 के सामने तालिका में धारा 35कग के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाने वाली लागत की अधिकतम राशि से संबंधित कॉलम (4) में, "270 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 470 लाख रुपये" से संबंधित अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के स्थान पर "270 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 500 लाख रुपए" अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ग) धारा 35कग के तहत छूट, कंपनी अधिनियम की धारा 135 की अनुसूची VII और कंपनी (सीएसआर) नियमावली, 2014 के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।

[सं. 28/2016/फा.सं.वी.27015/1/2016-एसओ(नैट.कॉम)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2016

**S.O.1511 (E).—** Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.92(E) dated the 2<sup>nd</sup> February, 1996, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 5, “Conduct eye operation, polio operation camps, oxygen cylinder seva and ambulance service all over Gujarat” by “Karuna Trust, 22, Gautam Nagar, Near Naranpura-Railway Crossing, Ahmedabad-13”, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1996-1997, which was extended further vide notification number S.O.57(E) dated the 16<sup>th</sup> January, 1998 for a period of three years beginning with assessment year 1999-2000; which was extended further vide notification number S.O.539(E) dated the 20<sup>th</sup> June, 2001 for a period of three years beginning with assessment year 2002-2003; which was extended further vide notification number S.O.143(E) dated the 2<sup>nd</sup> February, 2005 for a period of three years beginning with financial year 2004-2005; which was extended further vide notification number S.O.1307(E) dated 4<sup>th</sup> June, 2008 for a period of three years beginning with financial year 2007-08 and which was further extended vide notification number S.O. 3861(E) dated 27.12.2013 for a period of three years ending with financial year 2015-16;

And whereas by notification number S.O.539(E) dated the 20<sup>th</sup> June, 2001 the estimated cost was enhanced from Rs. 94.00 lakh to Rs.128.00 lakh; vide notification number S.O.1307(E) dated 4<sup>th</sup> June, 2008 the estimated cost was enhanced further from Rs. 128.00 lakh to 153.00 lakh and whereas by notification number S.O 3861(E) dated 27.12.2013 the estimated cost was enhanced from Rs.153 lakh to Rs.200 lakh and whereas by notification number S.O 472(E) dated 11.2.2015 the estimated cost was enhanced from Rs.200 lakh to Rs.470 lakh including a corpus fund of Rs.270 lakh;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 18 years;

And whereas the project cost of Rs.470 lakh including a corpus fund of Rs.270 lakh is likely to be amended to Rs.500 lakh including a corpus fund of Rs.270 lakh;

And, whereas, the National Committee for the Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years and for enhancing the project cost from Rs.470 lakh including a corpus fund of Rs.270 lakh to Rs.500 lakh including a corpus fund of Rs.270 lakh. However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (a) hereby notifies the scheme

or project "Conduct eye operation, polio operation camps, oxygen cylinder seva and ambulance service all over Gujarat" by "Karuna Trust, 22, Gautam Nagar, Near Naranpura-Railway Crossing, Ahmedabad-13, for a further period of three years beginning with the financial year 2016-17 i.e. 2016-17, 2017-18 and 2018-19 ;

“

(b) further amends the said notification number S.O. 92(E) dated the 2<sup>nd</sup> February, 1996, to the following effect, namely:-

'In the said notification, in the Table against serial number (5), in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and words "Rs.470 lakh including a corpus fund of Rs.270 lakh", the letters, figures and words "Rs.500 lakh including a corpus fund of Rs.270 lakh" shall be substituted'.

(b). The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No.28/2016 / F.No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA,Dy. Secy. (National Committee)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

**का. आ.1512 (अ).-** जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 08.08.1995 की अधिसूचना सं. का. आ. 713 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "श्री रामकृष्ण सेवाश्रम (स्वामी विवेकानंद एकीकृत ग्रामीण चिकित्सा केन्द्र श्री शरदा देवी नेत्र चिकित्सालय), स्वामी विवेकानंद नगर, पवागडा-561202, तुमकुर जिला, कर्नाटक" द्वारा "कुष्ठ रोग और क्षयरोग के उन्मूलन के लिए 30 बिस्तरों वाले स्वामी विवेकानंद एकीकृत ग्रामीण केन्द्र के निर्माण, स्थापना और संचालन" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 1.15 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 02 पर अधिसूचित किया था; जिसे बाद में दिनांक 11.02.1999 की अधिसूचना सं० सां० आ० 99 (अ०) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2001-02 को समाप्त होने वाले तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 12.12.2001 की अधिसूचना सं. का. आ. 1217 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-05 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 23.03.2005 की अधिसूचना सं. का. आ. 386 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 20.03.2007 की अधिसूचना सं. का. आ. 496 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था ; जिसे बाद में दिनांक 21.07.2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 1791 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 12.03.2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 629 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 20.03.2007 की अधिसूचना सं० सां० आ० 496 (अ०) के द्वारा परियोजना लागत को 142 लाख रुपये से बढ़ाकर 292 लाख रुपये कर दिया गया था और जबकि दिनांक 6 जनवरी, 2015 की अधिसूचना सं. का. आ. 63 (अ) के द्वारा परियोजना लागत को 292 लाख रुपये से बढ़ाकर 8.00 करोड़ रुपये कर दिया गया था।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के इक्कीस वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है। तथापि, धारा 35 क ग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (क) एतद्वारा "श्री रामकृष्ण सेवाश्रम (स्वामी विवेकानंद एकीकृत ग्रामीण

चिकित्सा केन्द्र श्री शारदा देवी नेत्र चिकित्सालय), स्वामी विवेकानंद नगर, पवागडा-561202, तुमकुर जिला, कर्नाटक" द्वारा चलाई जा रही "कुष्ठ रोग और क्षयरोग के उन्मूलन के लिए 30 बिस्तरों वाले स्वामी विवेकानंद एकीकृत ग्रामीण केन्द्र के निर्माण, स्थापना और संचालन" की परियोजना अथवा स्कीम को 8.00 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए अधिसूचित करती है;

(ख) धारा 35 कग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।

[सं. 29/2016 /फा. सं. वी -27015/1/2016 एस ओ( एन. सी)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2016

**S.O.1512 (E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number SO.713(E) dated 08.08.1995 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 2, "Construction, establishment and running of 30 bed Swami Vivekananda Integrated Rural centre for elimination of leprosy and Tuberculosis" by "Sri Ramakrishna Sevashrama (Swami Vivekananda Integrated Rural Health Centre Shree Sharada Devi Eye Hospital), Swami Vivekananda Nagar, Pavagada-561202, Tumkur district, Karnataka.", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.1.15 crore for a period of three years ending with financial year 1998-99; which was further extended vide notification number S.O.99(E) dated 11.02.1999 for three years ending with financial year 2001-02; which was further extended vide notification number S.O.1217(E) dated 12.12.2001 for three years ending with financial year 2004-05; which was further extended vide notification number SO.No.386(E) dated 23.03.2005 for three years ending with financial year 2006-07; which was further extended vide notification number S.O.496(E) dated 20.03.2007 for three years ending with financial year 2009-10; which was further extended vide notification number S.O. 1791(E) dated 21.7.2010 for three years ending with financial year 2012-13 and which was further extended vide notification number S.O. 629(E) dated 12.3.2013 for a period of three years ending with financial year 2015-16;

And whereas vide notification number S.O.496(E) dated 20.03.2007, the project cost was enhanced from 'Rs. 142 lakh' to 'Rs. 292 lakh' and whereas vide notification number S.O. 63(E) dated 6<sup>th</sup> January, 2015, the project cost was enhanced from 'Rs. 292 lakh' to 'Rs. 8.00 crore' ;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 21 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years. However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (a) hereby notifies the scheme or project "Construction, establishment and running of 30 bed Swami Vivekananda Integrated Rural centre for elimination of leprosy and Tuberculosis" which is being carried out by "Sri Ramakrishna Sevashrama (Swami Vivekananda Integrated Rural Health Centre Shree Sharada Devi Eye Hospital), Swami Vivekananda Nagar, Pavagada-561202, Tumkur district, Karnataka.", without any change in the approved cost of Rs. 8.00 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with the financial year 2016-17 i.e. 2016-17, 2017-18 and 2018-19;

(b). The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No. 29/2016 / F.No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

**का. आ.1513 (अ).**— जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 29 मार्च 2007 की अधिसूचना सं. का. आ. 466 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “बाल कल्याण दिल्ली परिषद्, कुदसिया बाग, यमुना मार्ग, सिविल लाईन्स, दिल्ली-110054” द्वारा “आंगनवाड़ी कामगारों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र, विकलांग बच्चों के आर्थोपेडिक केन्द्र पडोसी राज्यों के लिए आर्थोपेडिक आउटरीच कार्यक्रम, मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए बालचेतना कार्यक्रम, झुग्गी झोपड़ी और पुनर्वास क्षेत्रों के लिए क्रेच कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, कामकाजी बच्चों के लिए कार्यक्रम, निगरानी में गृह कार्य की स्कीम, बिछड़े बच्चों के लिए पालना गृह और पालना गोद कार्यक्रम, प्रायोजन कार्यक्रम, सहायक सेवाएं” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2007-08 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं 34 पर अधिसूचित किया था; जिसे बाद में दिनांक 22.03.2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 640 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाले तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 17.10.2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 333 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 11.02.2015 की अधिसूचना सं. का. आ. 475 (अ) के द्वारा परियोजना लागत को 10.83 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 16.26 करोड़ रुपये कर दिया गया था।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है। तथापि, धारा 35 क ग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (क) एतद्वारा “बाल कल्याण दिल्ली परिषद्, कुदसिया बाग, यमुना मार्ग, सिविल लाईन्स, दिल्ली-110054” द्वारा चलाई जा रही “आंगनवाड़ी कामगारों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र, विकलांग बच्चों के आर्थोपेडिक केन्द्र पडोसी राज्यों के लिए आर्थोपेडिक आउटरीच कार्यक्रम, मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए बालचेतना कार्यक्रम, झुग्गी झोपड़ी और पुनर्वास क्षेत्रों के लिए क्रेच कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, कामकाजी बच्चों के लिए कार्यक्रम, निगरानी में गृह कार्य की स्कीम, बिछड़े बच्चों के लिए पालना गृह और पालना गोद कार्यक्रम, प्रायोजन कार्यक्रम, सहायक सेवाएं” की परियोजना अथवा स्कीम को 16.26 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए अधिसूचित करती है;

(ख) धारा 35 क ग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।

[सं. 30/2016 /फा. सं. वी -27015/1/2016 एस ओ( एन. सी)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th April, 2016

**S.O.1513 (E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 466(E) dated the 29<sup>th</sup> March, 2007, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 34, “Anganwadi workers’ training center, Orthopedic centre for handicapped children, Orthopedic outreach programme for neighboring states, Balchethna programme for mentally challenged children, Creche programme for slum & resettlement areas, Vocational training programme, Working children’s programme, Supervised home work scheme, Palna home for abandoned

children and Palana adoption programme, Sponsorship programme, Auxiliary services” by “Delhi Council for Child Welfare, Qudsia Bagh, Yamuna Marg, Civil Lines, Delhi 110054”, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2007-08; which was further extended vide notification number S.O 640(E) dated 22.3.2010 for a period of three years ending with financial year 2012-13 and which was further extended vide notification number S.O. 3033(E) dated 17.10.2013 for a period of three years ending with financial year 2015-16;

And whereas vide notification number S.O.475(E) dated 11.2.2015, the project cost was enhanced from Rs. 10.83 crore to Rs. 16.26 crore;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 9 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years. However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (a) hereby notifies the scheme or project “Anganwadi workers’ training center, Orthopedic centre for handicapped children, Orthopedic outreach programme for neighboring states, Balchetna programme for mentally challenged children, Creche programme for slum & resettlement areas, Vocational training programme, Working children’s programme, Supervised home work scheme, Palna home for abandoned children and Palana adoption programme, Sponsorship programme, Auxiliary services” which is being carried out by “Delhi Council for Child Welfare, Qudsia Bagh, Yamuna Marg, Civil Lines, Delhi 110054”, without any change in the approved cost of Rs. 16.26 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with the financial year 2016-17 i.e. 2016-17, 2017-18 and 2018-19;

(b). The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No. 30/2016 / F.No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

**का. आ.1514 (अ).-** जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 20 सितंबर, 2001 की अधिसूचना सं. का. आ. 901 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “श्री रमण महर्षि नेत्रहीन अकादमी, सीए- 1 बी, तीसरा क्रॉस, तीसरा फेज, जेपी नगर, बेंगलुरु-560078” द्वारा “बेंगलुरु, कर्नाटक और इसके इर्द गिर्द के स्थानों पर विकलांगों/ नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए छात्रावास और पुस्तकालय का निर्माण और पुनर्वास/ कल्याण कार्यक्रमों का संचालन ” की परियोजना को निर्धारण वर्ष 2002-03 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 08 पर अधिसूचित किया था; जिसे बाद में दिनांक 25.05.2005 की अधिसूचना सं. का. आ. 716 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-05 को प्रारम्भ होने वाले तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 04.06.2008 की अधिसूचना सं. का. आ. 1296 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 को प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 22.03.2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 1296 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-2011 को प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 12.03.2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 655 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 को प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के पन्द्रह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है। तथापि, धारा 35

कग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (क) एतद्वारा “बाल कल्याण दिल्ली परिषद्, कुदसिया बाग, यमुना मार्ग, सिविल लाईन्स, दिल्ली-110054” द्वारा चलाई जा रही “श्री रमण महर्षि नेत्रहीन अकादमी, सीए- 1 बी, तीसरा क्रॉस, तीसरा फेज, जेपी नगर, बेंगलुरु-560078” द्वारा चलाई जा रही “बेंगलुरु, कर्नाटक और इसके इर्द गिर्द के स्थानों पर विकलांगों/ नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए छात्रावास और पुस्तकालय का निर्माण और पुनर्वास/ कल्याण कार्यक्रमों का संचालन ” की परियोजना अथवा स्कीम को 197.00 लाख रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए अधिसूचित करती है;

(ख) धारा 35 कग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।

[सं. 31/2016 /फा. सं. वी -27015/1/2016 एस ओ( एन. सी)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2016

**S.O.1514 (E).—** Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.901(E) dated the 20<sup>th</sup> September, 2001, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 8, “Construction of dormitory-cum-library and running of rehabilitation/welfare programmes for disabled/blind persons at Bangalore, Karnataka and its surrounding places” by “Shri Ramana Maharishi Academy of the Blind, CA-1B, 3<sup>rd</sup> Cross, 3<sup>rd</sup> Phase, J.P. Nagar, Bangalore-560078”, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with Assessment year 2002-2003, which was extended further vide notification number S.O.716(E) dated the 25<sup>th</sup> May, 2005 for a period of three years beginning with financial year 2004-2005 and which was extended further vide notification number S.O. No. 1296 (E) dated 4.06.2008 for three years beginning with financial Year 2007-08 and which was extended further vide notification number S.O.1296(E) dated 22<sup>nd</sup> March, 2010 for a period of three year beginning with financial year 2010-11 and which was extended further vide notification number S.O.655(E) dated 12<sup>th</sup> March, 2013 for a period of three year beginning with financial year 2015-16;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond fifteen years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years. However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (a) hereby notifies the scheme or project “Construction of dormitory-cum-library and running of rehabilitation/welfare programmes for disabled/blind persons at Bangalore, Karnataka and its surrounding places” which is being carried out by “Shri Ramana Maharishi Academy of the Blind, CA-1B, 3<sup>rd</sup> Cross, 3<sup>rd</sup> Phase, J.P. Nagar, Bangalore-560078”, without any change in the approved cost of Rs.197.00 lakh, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with financial year 2016-17 i.e. 2016-17, 2017-18 and 2018-19.

(b). The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No.31/2016 / F.No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

**का. आ. 1515 (अ).**— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 07.10.2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 3033 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “सहयोग केयर फॉर यू, जीएच 14/757, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110087” द्वारा “(i) व्यावसायिक परियोजना-पर्यायवर्ण स्वच्छता और साफ-सफाई कार्यक्रम (ii) महिलाओं के लिए प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम (iii) क्रेच सेवाएं और शैक्षणिक कार्यक्रम (iv) आवारा बच्चों और कामकाजी बच्चों के लिए शिक्षा परियोजना” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2015-16 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 4.22 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 06 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है। तथापि, धारा 35 क ग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (क) एतद्वारा “सहयोग केयर फॉर यू, जीएच 14/757, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110087” द्वारा चलाई जा रही “(i) व्यावसायिक परियोजना-पर्यायवर्ण स्वच्छता और साफ-सफाई कार्यक्रम (ii) महिलाओं के लिए प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम (iii) क्रेच सेवाएं और शैक्षणिक कार्यक्रम (iv) आवारा बच्चों और कामकाजी बच्चों के लिए शिक्षा परियोजना” की परियोजना अथवा स्कीम को 4.22 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए अधिसूचित करती है;

(ख) धारा 35 क ग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।

[सं. 32/2016 /फा. सं. वी -27015/1/2016 एस ओ( एन. सी)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th April, 2016

**S.O.1515 (E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 3033(E) dated 7.10.2013 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 6, “(i) Vocational Project - Environmental Hygiene and Sanitation Programme (ii) Adult Literacy Programme for Women (iii) Crèche Services and Educational Programme (iv) Street Children and working Children Education Project” by “Sahyog Care for You, GH 14/757, Paschim Vihar, New Delhi 110 087”, as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 4.22 crore for a period of three years ending with financial year 2015-16;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years. However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (a) hereby notifies the scheme or project “(i)



Vocational Project - Environmental Hygiene and Sanitation Programme (ii) Adult Literacy Programme for Women (iii) Crèche Services and Educational Programme (iv) Street Children and working Children Education Project”, which is being carried out by “Sahyog Care for You, GH 14/757, Paschim Vihar, New Delhi 110 087”, as an eligible project or scheme for a further period of three years, without any change in the approved cost of Rs. 4.22 crore commencing with the financial year 2016-17 i.e. 2016-17, 2017-18 and 2018-19;

(b). The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No. 32 /2016 / F.No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

**का. आ.1516 (अ).-** जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 18 मार्च 2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 614 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “श्री श्री 108 करुणामयी काली माता मंदिर, 107/1, डॉ. मेघनाद साह सरानी, कलकत्ता-700029” द्वारा “वृद्धाश्रम का विस्तार” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 400 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 666.07 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 29 पर अधिसूचित किया था; जिसे बाद में दिनांक 17.10.2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 3170 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 को प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 17.10.2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 3170 (अ) के द्वारा परियोजना लागत को 400.00 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 666.07 लाख रुपये से बढ़ाकर 400.00 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 856.97 लाख रुपये कर दिया गया था।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है। तथापि, धारा 35 क ग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (क) एतद्वारा “श्री श्री 108 करुणामयी काली माता मंदिर, 107/1, डॉ. मेघनाद साह सरानी, कलकत्ता-700029” द्वारा चलाई जा रही “वृद्धाश्रम का विस्तार” की परियोजना अथवा स्कीम को 400.00 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 856.97 लाख रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए अधिसूचित करती है;

(ख) इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा दिनांक 18 मार्च 2010 की उक्त अधिसूचना सं. का. आ. 614 (अ) को निम्नलिखित आशय से संशोधित करती है, नामतः -

‘उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 29 के सामने तालिका में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली लागत की अधिकतम राशि से संबंधित कालम (4) में “400.00 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 856.97 लाख रुपये” से संबंधित अक्षरों, अंकों और शब्दों को “700.00 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 1500.00 लाख रुपये” से संबंधित अक्षरों, अंकों और शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ग) धारा 35 कग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।

[सं. 33/2016 /फा. सं. वी -27015/1/2016 एस ओ( एन. सी)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2016

**S.O.1516 (E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 614 (E) dated 18<sup>th</sup> March, 2010 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 29 “Expansion of Old Age Home” by “Sree Sree 108 Karunamoyee Kalimata Mandir, 107/1, Dr. Meghnad Saha Sarani, Calcutta 700029”, as an eligible project at the estimated cost of Rs 666.07 lakh including a corpus fund of Rs. 400.00 lakhs, for a period of three years ending with financial year ending with financial year 2012-13 and which was extended further vide notification number S.O. 3170(E) dated 17<sup>th</sup> October, 2013 for a period of three year beginning with financial year 2015-16;

And whereas vide notification number S.O. 3170(E) dated 17<sup>th</sup> October, 2013, the project cost was enhanced from Rs.666.07 lakh including a corpus fund of Rs.400.00 lakh to Rs. 856.97 lakh including a Corpus Fund of Rs.400.00 Lakh;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 6 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years. However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961),- (a) hereby notifies the scheme or project “Expansion of Old Age Home” which is being carried out by “Sree Sree 108 Karunamoyee Kalimata Mandir, 107/1, Dr. Meghnad Saha Sarani, Calcutta 700029”, as an eligible project or scheme, without any change in the approved cost of Rs. 856.97 lakh including a Corpus Fund of Rs.400.00 Lakh commencing with the financial year 2016-17 i.e. 2016-17, 2017-18 and 2018-19;

(b) Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby amends the said notification number S.O. 614 (E) dated 18<sup>th</sup> March, 2010, to the following effect, namely:

‘In the said notification, in the Table against serial number (29), in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and words “Rs. 856.97 lakh including a Corpus Fund of Rs. 400.00 Lakh”, the letters, figures and words “Rs.1500.00 lakh including a corpus fund of Rs. 700.00 lakh” shall be substituted’.

(c) The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No.33/2016 / F.No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

**का. आ.1517 (अ).**- जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 23.12. 2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 3021(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “अभय आश्रय, पोओ असैगोली 574199, कोनाजे गांव, मंगलौर तालुका, डी.के. जिला, कर्नाटक” द्वारा “वृद्धाश्रम के लिए आवर्ती लागत, मानसिक और शारीरिक रूप से अशक्त वृद्ध व्यक्तियों के लिए घर, निराश्रित बच्चों के लिए घर और 50 लाख रुपये की कॉर्पस निधि के लिए आवर्ती व्यय” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 50

लाख रुपये की कॉर्पस निधि सहित 3.40 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 3 पर अधिसूचित किया था और जिसे बाद में दिनांक 31 जुलाई, 2014 की अधिसूचना सं. का. आ. 1933 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम को छह वर्षों से आगे बढ़ने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है। तथापि, धारा 35 कग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (क) एतद्वारा “अभय आश्रय, पोओ असैगोली 574199, कोनाजे गांव, मंगलूर तालुका, डी.के. जिला, कर्नाटक” द्वारा चलाई जा रही “वृद्धाश्रम के लिए आवर्ती लागत, मानसिक और शारीरिक रूप से आशक्त वृद्ध व्यक्तियों के लिए घर, निराश्रित बच्चों के लिए घर और 50 लाख रुपये की कॉर्पस निधि के लिए आवर्ती व्यय” की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए 50 लाख रुपये की कॉर्पस निधि सहित 3.40 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है;

(ख) धारा 35 कग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।

[सं. 34/2016 /फा. सं. वी.27015/1/2016 एस ओ( एन. सी.)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2016

**S.O.1517 (E).—** Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.3021(E) dated 23.12.2010 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 3, “Recurring cost of old age home, home for physically and mentally challenged older persons, recurring expenses of home for destitute children and for a corpus fund of Rs.50 lakh” by “Abhaya Ashraya, PO Assaigoli 574199, Konaje Village, Mangalore Taluka, D.K. District, Karnataka”, as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.3.40 crore including corpus fund of Rs.50 lakh, for a period of three years ending with financial year 2012-13 and which was extended further vide notification number S.O. 1933(E) dated 31<sup>st</sup> July, 2014 for a period of three year beginning with financial year 2015-16;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 6 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years. However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (a) hereby notifies the scheme or project “Recurring cost of old age home, home for physically and mentally challenged older persons, recurring expenses of home for destitute children and for a corpus fund of Rs.50 lakh”, which is being carried out by “Abhaya Ashraya, PO Assaigoli 574199, Konaje Village, Mangalore Taluka, D.K. District, Karnataka”, without any change in the approved cost of Rs.3.40 crore including corpus fund of Rs.50 lakh, for a further period of three years commencing with the financial year 2016-17 i.e. 2016-17, 2017-18 and 2018-19;

(b). The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No.34 /2016 / F.No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

**का. आ.1518 (अ).-** जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 23.12. 2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 3021(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “राजा चेरिटेबल मेडिकल ट्रस्ट, पी.बी. सं. 34, मुत्थुवट्टूर, चवाक्कड-680506, त्रिचुर जिला, केरल” द्वारा “आउटरीच केयरिंग हैंड्स” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 4.06 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 17 पर अधिसूचित किया था और जिसे बाद में दिनांक 17 अक्टूबर, 2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 3136 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम को छह वर्षों से आगे बढ़ने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है। तथापि, धारा 35 क ग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (क) एतद्वारा “राजा चेरिटेबल मेडिकल ट्रस्ट, पी.बी. सं. 34, मुत्थुवट्टूर, चवाक्कड-680506, त्रिचुर जिला, केरल” द्वारा चलाई जा रही “आउटरीच केयरिंग हैंड्स” की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए 4.06 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है;

(ख) धारा 35 क ग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।

[सं. 35/2016 /फा. सं. वी.27015/1/2016 एस ओ( एन. सी.)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th April, 2016

**S.O.1518 (E).—** Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 3021 (E) dated 23<sup>rd</sup> December, 2010 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 17 “Outreach Caring Hands” by “Rajah Charitable Medical Trust, P.B. No. 34, Muthuvattoor, Chavakkad-680506, Trichur Dist, Kerala”, as an eligible project at the estimated cost of Rs.4.06 crore for a period of three years ending with financial year 2012-13 and which was extended further vide notification number S.O. 3136(E) dated 17<sup>th</sup> October, 2013 for a period of three year beginning with financial year 2015-16;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 6 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years. However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (a) hereby notifies the scheme or project “Outreach Caring Hands” which is being carried out by “Rajah Charitable Medical Trust, P.B. No. 34, Muthuvattoor, Chavakkad-680506, Trichur Dist, Kerala”, without any change in the approved cost of Rs.4.06 crore, as

an eligible project or scheme, for a further period of three years commencing with financial year 2016-17 i.e. 2016-17, 2017-18 and 2018-19;

(b). The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No.35/2016 / F.No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

**का. आ.1519 (अ).**- जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 29 मार्च, 2007 की अधिसूचना सं. का. आ. 466 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “डवलेपमेंट इनिशिएटिव फॉर सेल्फ-हेल्प एंड एवेकनिंग (डीआईएसएचए), मार्फत समाज सेवा केंद्र, क्रम सं. 4272, अकुरदी पोस्ट आफिस के पीछे, अकुरदी, पुणे-411035” द्वारा “क्षमता निर्माण के द्वारा गरीबी उन्मूलन, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बाजार से सहायता और माइक्रो क्रेडिट योजना” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2007-08 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 18 पर अधिसूचित किया था; जिसे बाद में दिनांक 11.10.2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 2523 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 27 दिसंबर, 2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 3844 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम को नौ वर्षों से आगे बढ़ने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है। तथापि, धारा 35 क ग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (क) एतद्वारा “डवलेपमेंट इनिशिएटिव फॉर सेल्फ-हेल्प एंड एवेकनिंग (डीआईएसएचए), मार्फत समाज सेवा केंद्र, क्रम सं. 4272, अकुरदी पोस्ट आफिस के पीछे, अकुरदी, पुणे-411035” द्वारा चलाई जा रही “क्षमता निर्माण के द्वारा गरीबी उन्मूलन, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बाजार से सहायता और माइक्रो क्रेडिट योजना” की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए 163.06 लाख रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है;

(ख) धारा 35 क ग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।

[सं. 36/2016 / फा. सं. वी.27015/1/2016 एस ओ( एन. सी.)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2016

**S.O.1519 (E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 466(E) dated 29<sup>th</sup> March, 2007, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 18, Poverty alleviation through capacity building, market support and micro-credit programme for economically weaker section of the society by ‘Development Initiative for Self-Help and Awakening (DISHA) C/o. Samaj Seva Kendra, Sr. No. 4272, Behind Akurdi Post Office, Akurdi, Pune-411035’, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with

financial year 2007-08; which was further extended vide notification S.O. No.2523(E) dated 11.10.2010 for a period of three years ending with financial year 2012-13 and which was extended further vide notification number S.O. 3844(E) dated 27<sup>th</sup> December, 2013 for a period of three years ending with financial year 2015-16;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond nine years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years. However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (a) hereby specifies the scheme or project "Poverty alleviation through capacity building, market support and micro-credit programme for economically weaker section of the society", is being carried out by Development Initiative for Self-Help and Awakening (DISHA).C/o. Samaj Seva Kendra, Sr. No. 4272, Behind Akurdi Post Office, Akurdi, Pune-411035, without any change in the approved cost of Rs. 163.06 lakh, as an eligible project or scheme for a further period of three financial years commencing with the financial year 2016-17 i.e. 2016-17, 2017-18 and 2018-19;

(b). The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No.36/2016 / F.No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

**का. आ.1520 (अ).**- जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 18.03.2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 614(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "वल्लुवर गुरुकुलम, 220 जी एस टी रोड, तंबारम पश्चिम, चेन्नै- 600045" द्वारा "कला भवनम" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2010-11 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 2.38 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 16 पर अधिसूचित किया था और जिसे बाद में दिनांक 27 दिसंबर, 2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 3833 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम को छह वर्षों से आगे बढ़ने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है। तथापि, धारा 35 क ग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (क) एतद्वारा "वल्लुवर गुरुकुलम, 220 जी एस टी रोड, तंबारम पश्चिम, चेन्नै- 600045" द्वारा चलाई जा रही "कला भवनम" की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए 2.38 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है;

(ख) धारा 35 क ग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।

[सं. 37/2016 /फा. सं. वी.27015/1/2016 एस ओ( एन. सी.)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th April, 2016

**S.O.1520 (E).**— Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.614(E) dated 18.03.2010, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 16, “Kala Bhavanam” by “Valluvar Gurukulam, 220, G S T Road, Tambaram West, Chennai-600045”, at the estimated cost of Rs. 2.38 crore, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2010-11 and which was extended further vide notification number S.O. 3833(E) dated 27<sup>th</sup> December, 2013 for a period of three year ending with financial year 2015-16;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years. However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), - (a) hereby notifies the scheme or project “Kala Bhavanam”, which is being carried out by “Valluvar Gurukulam, 220, G S T Road, Tambaram West, Chennai-600045”, without any change in the approved cost of Rs. 2.38 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial years, financial year 2016-17 i.e. 2016-17, 2017-18 and 2018-19;

(b). The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No.37 /2016 / F.No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

**का. आ.1521 (अ).**— जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 29 मार्च, 2007 की अधिसूचना सं. का. आ. 466 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “भारती फाउंडेशन, एच-5/12, कुतुब एम्ब्रीयंस, महरौली रोड, नई दिल्ली-110030” द्वारा “सत्य भारती विद्यालयों (500 प्राथमिक विद्यालयों और साथ ही साथ अनौपचारिक शिक्षा की स्थापना और सहायता प्रदान करना)” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2007-08 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 1 पर अधिसूचित किया था; जिसे बाद में दिनांक 22 मार्च, 2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 648 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 17.10. 2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 3643 (अ) (दिनांक 11.12.2013 के शुद्धिपत्र सं. का. आ. 3643 (अ) के साथ पठित) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 21 जनवरी, 2009 की अधिसूचना सं. 247(अ) के द्वारा अनुमानित लागत को 10.00 करोड़ रुपये की कॉर्पस निधि सहित 35.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 30 करोड़ रुपये की कॉर्पस निधि सहित 115.00 करोड़ रुपये कर दिया गया था; आगे, दिनांक 11.10.2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 2529(अ) के द्वारा योजना लागत को 30.00 करोड़ रुपये की कॉर्पस निधि सहित 115.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 45.00 करोड़ रुपये की कॉर्पस निधि सहित 115 करोड़ रुपये कर दिया गया था और अधिसूचना सं. 1879(अ) के द्वारा परियोजना लागत को 45 करोड़ रुपये की कॉर्पस निधि सहित 115 करोड़ रुपये से और आगे बढ़ाकर 60 करोड़ रुपये की कॉर्पस निधि सहित 160 करोड़ रुपये कर दिया गया था और दिनांक 11.2.2015 की अधिसूचना सं. 447(अ.) के द्वारा परियोजना लागत को 60 करोड़ रुपये की कॉर्पस निधि सहित 160 करोड़ रुपये से और आगे बढ़ाकर 110 करोड़ रुपये की कॉर्पस निधि सहित 360 करोड़ रुपये कर दिया गया था;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है। तथापि,

धारा 35 कग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (क) एतद्वारा “भारती फाउंडेशन, एच-5/12, कुतुब एम्बीयंस, महरौली रोड, नई दिल्ली-110030” द्वारा चलाई जा रही “सत्य भारती विद्यालय (500 प्राथमिक विद्यालयों और साथ ही साथ अनौपचारिक शिक्षा की स्थापना और सहायता प्रदान करना)” की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए 360.00 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है;

(ख) धारा 35 कग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।

[सं. 38/2016 /फा. सं. वी.27015/1/2016 एस ओ (एन. सी.)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2016

**S.O.1521 (E).**— Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.466(E) dated the 29<sup>th</sup> March, 2007, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 1, “Satya Bharti Schools (establishing & supporting 500 primary schools as well as non-formal education)” by “Bharti Foundation, H-5/12, Qutub Ambience, Mehrauli Road, New Delhi – 110030”, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2007-2008; which was extended further vide notification number S.O.648(E) dated 22<sup>nd</sup> March, 2010 for a period of three years beginning with financial years 2010-11 and the project was further extended vide notification number S.O. 3643(E) dated 17.10.2013(read with corrigendum S.O. No. 3643(E) dated 11.12.2013) for a period of three years ending with financial year 2015-16;

And whereas by notification number 247(E) dated 21<sup>st</sup> January, 2009, the estimated cost was enhanced from Rs.35.00 crore including a corpus fund of Rs.10.00 crore to Rs. 115.00 crore including a corpus fund of Rs. 30.00 crore; further, vide notification S.O. 2529(E) dated 11.10.2010 the project cost was changed from Rs. 115 crore including a corpus fund of Rs. 30 crore to Rs. 115 crore including a corpus fund of Rs. 45 crore and vide notification number 1879(E) the project cost was further enhanced from Rs. 115 crore including a corpus fund of Rs. 45 crore to Rs.160 crore including a corpus fund of Rs.60 crore and vide notification number 447(E) dated 11.2.2015 the project cost was further enhanced from ‘Rs.160.00 crore including corpus fund of Rs.60.00 crore’ to ‘Rs.360.00 crore including corpus fund of Rs.110.00 crore’;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years. However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (a) hereby notifies the scheme or project “Satya Bharti Schools (establishing & supporting 500 primary schools as well as non-formal education)”, which is being carried out by “Bharti Foundation, H-5/12, Qutub Ambience, Mehrauli Road, New Delhi – 110030”, without any change in the approved cost of Rs.360 crore including corpus fund of Rs.110 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial years, financial year 2016-17 i.e. 2016-17, 2017-18 and 2018-19;

(b). The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No.38/2016 / F.No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)



**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

**का. आ.1522 (अ).-** जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 16.05.2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 1253 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “विश्वास - विजन फॉर हेल्थ, वेल्फेयर एंड स्पेशल नीड्स, सी-6/53, सफदरजंग डेवलेपमेंट एरिया, नई दिल्ली-110016” द्वारा “रिसोर्स डेवलेपमेंट ऑन सस्टेनेबल इन्क्लूसिव प्रेक्टिसिस” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2015-16 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 10.00 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 12.00 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 8 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है। तथापि, धारा 35 क ग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (क) एतद्वारा “विश्वास - विजन फॉर हेल्थ, वेल्फेयर एंड स्पेशल नीड्स, सी-6/53, सफदरजंग डेवलेपमेंट एरिया, नई दिल्ली-110016” द्वारा चलाई जा रही “रिसोर्स डेवलेपमेंट ऑन सस्टेनेबल इन्क्लूसिव प्रेक्टिसिस” की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए 10.00 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 12.00 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है;

(ख) धारा 35 क ग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।

[सं. 39/2016 /फा. सं. वी -27015/1/2016 एस ओ( एन. सी)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th April, 2016

**S.O.1522 (E).—** Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1253(E) dated 16.5.2013 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 8, “Resource Development on Sustainable Inclusive Practices” by “Vishwas – Vision for health, welfare and special needs, C-6/53, Safdarjung Development Area, New Delhi – 110 016”, as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 12.00 crore including a corpus fund of Rs. 10.00 crore for a period of three years ending with financial year 2015-16;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years. However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (a) hereby notifies the scheme or project “Resource Development on Sustainable Inclusive Practices”, which is being carried out by “Vishwas – Vision for health, welfare and special needs, C-6/53, Safdarjung Development Area, New Delhi – 110 016”, as an eligible project

or scheme for a further period of three years, without any change in the approved cost of Rs. 12.00 crore including a corpus fund of Rs. 10.00 crore commencing with the financial year 2016-17 i.e. 2016-17, 2017-18 and 2018-19;

(b). The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No.39 /2016 / F.No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

**का. आ.1523 (अ).-** जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 11.05.2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 1052 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “इंडियन मेडिकल सेंटर, पुराना नं. 283 (नया नं. 218), टी. टी. के. रोड, चेन्नई 18, तमिलनाडु” द्वारा व्यावसायिक शिक्षा के लिए नर्सरी स्कूल की स्थापना” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 14.17 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप क्रम सं. 04 पर अधिसूचित किया था; जिसे बाद में दिनांक 27.12.2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 3853 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है। तथापि, धारा 35 क ग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (क) एतद्वारा “इंडियन मेडिकल सेंटर, पुराना नं. 283 (नया नं. 218), टी. टी. के. रोड, चेन्नई 18, तमिलनाडु” द्वारा चलाई जा रही “व्यावसायिक शिक्षा के लिए नर्सरी स्कूल की स्थापना” की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए 14.17 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है;

(ख) धारा 35 क ग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।

[सं. 40/2016 /फा. सं. वी -27015/1/2016 एस ओ( एन. सी)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2016

**S.O.1523 (E).—** Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1052(E) dated 11.05.2010, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 4, “Establishment of school of Nursing for vocational education” by “Indian Medical Centre, Old No.283, (New No. 218), T.T.K. Road, Chennai 18, Tamil Nadu”, at the estimated cost of Rs.14.17 crore, as an eligible project or scheme for a period of three years ending with financial year 2012-13 and which was extended further vide notification number S.O. 3853(E) dated 27<sup>th</sup> December, 2013 for a period of three year ending with financial year 2015-16;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years. However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), - (a) hereby notifies the scheme or project "Establishment of school of Nursing for vocational education", which is being carried out by "Indian Medical Centre, Old No.283, (New No. 218), T.T.K. Road, Chennai 18, Tamil Nadu", without any change in the approved cost of Rs.14.17 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial years 2016-17 i.e. 2016-17, 2017-18 and 2018-19;

(b). The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[ No. 40/2016 / F.No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM) ]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

**का. आ.1524 (अ).**- जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 29.03.2007 की अधिसूचना सं. का. आ. 466 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "बेल्लूर, कृष्णमाचार एंव सेशम्मा स्मारक निधि न्यास, नं. 864, 25वां क्रॉस, 51 वां मेन, प्रथम स्तर, कुमारस्वामी लेआउट, बेंगलूर-560078" द्वारा "ग्रामीण समाज में विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से अन्य कमजोर वर्ग के लिए स्कूल और मेडिकल सेंटर एंव अस्पताल की स्थापना और संचालन" की परियोजना को 15.00 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 22.46 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर वित्तीय वर्ष 2009-10 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 03 पर अधिसूचित किया था; जिसे बाद में दिनांक 22.03.2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 659 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 17.10.2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 3162 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि परियोजना लागत को 15.00 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 22.46 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 26.00 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 41.46 करोड़ रुपये करने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने और परियोजना लागत को 15.00 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 22.46 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 26.00 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 41.46 करोड़ रुपये करने की सिफारिश की है। तथापि, धारा 35 क ग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियों (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (क) "बेल्लूर, कृष्णमाचार एंव सेशम्मा स्मारक निधि न्यास, नं. 864, 25वां क्रॉस, 51 वां मेन, प्रथम स्तर, कुमारस्वामी लेआउट, बेंगलूर-560078" द्वारा "ग्रामीण समाज में विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से अन्य कमजोर वर्ग के लिए स्कूल और मेडिकल सेंटर एंव अस्पताल की स्थापना और संचालन" की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए अधिसूचित करती है;

(ख) दिनांक 29.03.2007 की उक्त अधिसूचना सं. का. आ. 466 (अ) को निम्नलिखित आशय से संशोधित करती है, नामतः -

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं० 3 के सामने तालिका में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35कग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली लागत की अधिकतम राशि से संबंधित कालम (4) में "15.00 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 22.46 करोड़ रुपये" से संबंधित अक्षरों, अंकों और शब्दों को "26.00 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 41.46 करोड़ रुपये" से संबंधित अक्षरों, अंकों और शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ग) धारा 35 कग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।

[सं. 41/2016 /फा. सं. वी -27015/1/2016 एस ओ( एन. सी)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2016

**S.O.1524 (E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.466(E) dated 29<sup>th</sup> March, 2007 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 3, "Setting up and running of a school and a medical centre cum hospital, especially for SC/ST and other economically weaker sections of the rural society" by "Bellur Krishnamachar & Seshamma Smaraka Nidhi Trust, No. 864, 25th Cross, 51st Main, I stage, Kumaraswamy layout, Bangalore -560078", as an eligible project at the estimated cost of Rs.22.46 crore including a corpus fund of Rs. 15.00 crore for a period of three years ending with financial year 2009-10; which was further extended vide notification number S.O. 659 (E) dated 22<sup>nd</sup> March, 2010 for a period of three years ending with Financial year 2012-13 and the project was further extended vide notification number S.O. 3162(E) dated 17.10.2013 for a period of three years ending with financial year 2015-16;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 6 years;

And whereas the project cost is likely to enhance from Rs.22.46 crore including a corpus fund of Rs. 15.00 crore to Rs. 41.46 crore including a corpus fund of Rs. 26.00 crore;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years and for amending the project cost from Rs.22.46 crore including a corpus fund of Rs. 15.00 crore to Rs. 41.46 crore including a corpus fund of Rs. 26.00 crore. However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (a) hereby notifies the scheme or project "Setting up and running of a school and a medical centre cum hospital, especially for SC/ST and other economically weaker sections of the rural society" which is being carried out by "Bellur Krishnamachar & Seshamma Smaraka Nidhi Trust, No. 864, 25th Cross, 51st Main, I stage, Kumaraswamy layout, Bangalore -560078", as an eligible project or scheme, for a further period of three years commencing with financial year 2016-17 i.e. 2016-17, 2017-18 and 2018-19;

(b) further amends the said notification number S.O. 466(E) dated 29<sup>th</sup> March, 2007, to the following effect, namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 3, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section of 35AC of Income Tax Act, 1961 for the letters, figures and word "Rs.22.46 crore including a corpus fund of Rs. 15.00 crore" the letters, figures and word "Rs. 41.46 crore including a corpus fund of Rs. 26.00 crore" shall be substituted.

(c) The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No.41/2016 / F.No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

**का. आ.1525 (अ).-** जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 11 फरवरी, 1999 की अधिसूचना सं. का. आ. 96 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "करूणा सेतु ट्रस्ट, वाडनगर-384355, गुजरात" द्वारा "गुजरात में महसाना जिले के वाडनगर में अस्पताल का संचालन, उपस्करों की खरीद और कल्याणकारी गतिविधियां" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1999-2000 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 5 पर अधिसूचित किया था; जिसे बाद में दिनांक 10 जनवरी, 2001 की अधिसूचना सं. का. आ. 29 (अ) के द्वारा निर्धारण वर्ष 2002-2003 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 19 मार्च, 2004 की अधिसूचना सं. का. आ. 381 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-05 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 4 जून, 2008 की अधिसूचना सं० सां० आ० 1298 (अ०) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 17.05.2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 1146 (अ०) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 27.12.13 की अधिसूचना सं. का. आ. 3851 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 24 अक्टूबर, 2002 की अधिसूचना सं. 1120(अ) के द्वारा अनुमानित लागत को 67.48 रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की कॉर्पस निधि सहित 142.03 लाख रुपये कर दिया गया था; दिनांक 19 मार्च, 2004 की अधिसूचना सं. का. आ. 381(अ) के द्वारा अनुमानित लागत को 142.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 50.00 लाख रुपये की कॉर्पस निधि सहित 184.50 लाख रुपये कर दिया गया था; दिनांक 4 जून, 2008 की अधिसूचना सं. 1298 (अ) के द्वारा अनुमानित लागत को 50 लाख रुपये की कॉर्पस निधि सहित 184.50 लाख रुपये से और आगे बढ़ाकर 50 लाख रुपये की कॉर्पस निधि सहित 282.60 लाख रुपये कर दिया गया था और दिनांक 17.05.2010 की अधिसूचना सं. 1146(अ) के द्वारा अनुमानित लागत को 50 लाख रुपये की कॉर्पस निधि सहित 282.60 लाख रुपये से और आगे बढ़ाकर 50 लाख रुपये की कॉर्पस निधि सहित 373.60 लाख रुपये कर दिया गया था; और दिनांक 27.12.2013 की अधिसूचना सं. 3851(अ) के द्वारा अनुमानित लागत को 50 लाख रुपये की कॉर्पस निधि सहित 373.60 लाख रुपये से और आगे बढ़ाकर 50 लाख रुपये की कॉर्पस निधि सहित 679.20 लाख रुपये कर दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 18 वर्षों से आगे बढ़ने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है,

इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है। तथापि, धारा 35 क ग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।;

(क) एतद्वारा "करूणा सेतु ट्रस्ट, वाडनगर-384355, गुजरात" द्वारा चलाई जा रही "गुजरात में महसाना जिले के वाडनगर में अस्पताल का संचालन, उपस्करों की खरीद और कल्याणकारी गतिविधियां" की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए 50 लाख रुपये की कॉर्पस निधि सहित 679.20 लाख रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है;

(ख) धारा 35 क ग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।

[सं. 42/2016 /फा. सं. वी.27015/1/2016 एस ओ (एन. सी.) ]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th April, 2016

**S.O.1525 (E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.96(E) dated the 11<sup>th</sup> February, 1999, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 5, “Running of hospital, purchase of equipments and welfare activities at Vadnagar, Mehsana District, Gujarat” by “Karuna Setu Trust, Vadnagar-384355, Gujarat, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1999-2000, which was extended further vide notification number S.O.29(E) dated the 10<sup>th</sup> January, 2001 for a period of three years beginning with assessment year 2002-2003, which was extended further vide notification number S.O.381(E) dated the 19<sup>th</sup> March, 2004 for a period of three years beginning with financial year 2004-2005; which was extended further vide notification number S.O. 1298(E) dated 4<sup>th</sup> June, 2008 for a period of three financial year 2007-08; which was further extended vide S.O. No. 1146 (E) dated 17.05.2010 for a period of three years ending with financial year 2012-13 and which was further extended vide S.O. No. 3851(E) dated 27.12.2013 for a period of three years ending with financial year 2015-16;

And whereas by notification number S.O.1120(E) dated the 24<sup>th</sup> October, 2002 the estimated cost was enhanced from Rs. 67.48 lakh to Rs.142.03 lakh including a corpus fund of Rs.50.00 lakh; vide notification number S.O.381(E) dated the 19<sup>th</sup> March 2004 the estimated cost was further enhanced from Rs.142.00 lakh to Rs.184.50 lakh including a corpus fund of Rs.50.00 lakh; vide notification number S.O. 1298(E) dated 4<sup>th</sup> June, 2008 the estimated cost was further enhanced from Rs. 184.50 lakh including corpus fund of Rs. 50 lakh to Rs.282.60 lakh including corpus fund of Rs. 50 lakh; and vide notification number S.O. No. 1146 (E) dated 17.05.2010, the estimated cost was further enhanced from Rs.282.60 lakh including corpus fund of Rs. 50 lakh to 373.60 lakh including corpus fund of Rs. 50 lakh and vide notification number S.O. No. 3851 (E) dated 27.12.2013, the estimated cost was further enhanced from Rs. 373.60 lakh including corpus fund of Rs. 50 lakh to Rs.679.20 lakh including a corpus fund of Rs.50 lakh;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond eighteen years;

And, whereas, the National Committee for the Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years. However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961),-

a) hereby notifies the scheme or project “Running of hospital, purchase of equipments and welfare activities at Vadnagar, Mehsana District, Gujarat”, which is being carried out by Karuna Setu Trust, Vadnagar-384355, Gujarat without any change in the approved cost of Rs.679.20 lakh including a corpus fund of Rs.50 lakh, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial years 2016-17 i.e. 2016-17, 2017-18 and 2018-19;

(b) The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No. 42/2016 / F.No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

**का. आ.1526 (अ).**- जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 17 जून, 2008 की अधिसूचना सं. का. आ. 1462 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “इस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन, हरे कृष्णा लैंड, जुहू, मुंबई-400049” द्वारा “मध्याह्न भोजन परियोजना” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2009-10 को समाप्त होने वाली दो वर्ष की अवधि के लिए 853.90 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 10 पर अधिसूचित किया था; जिसे बाद में दिनांक 21 जुलाई, 2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 1788 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 17 अक्टूबर, 2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 3134 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 17 अक्टूबर, 2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 3134 (अ) के द्वारा अनुमानित लागत को 853.90 लाख रुपये से बढ़ाकर 2434.12 लाख रुपये कर दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के आठ वर्षों से आगे बढ़ने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है। तथापि, धारा 35 कग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (क) एतद्वारा “इस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन, हरे कृष्णा लैंड, जुहू, मुंबई-400049” द्वारा चलाई जा रही “मध्याह्न भोजन परियोजना” की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए 2434.12 लाख रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है;

(ख) धारा 35 कग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।

[सं. 43/2016 /फा. सं. वी.27015/1/2016 एस ओ( एन. सी.)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2016

**S.O.1526 (E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.1462 (E) dated 17<sup>th</sup> June, 2008 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 10, “Mid-day Meal Project” by the “Iskcon Food Relief Foundation, Hare Krishna Land, Juhu, Mumbai 400 049”, as an eligible project at the estimated cost of Rs.853.90 lakh crore for a period of two years ending with financial year 2009-10, which was further extended vide notification number S.O. 1788 (E) dated 21<sup>st</sup> July, 2010 for a period of three years ending with financial year 2012-13 and which was further extended vide notification number S.O. 3134 (E) dated 17<sup>th</sup> October, 2013 for a period of three years ending with financial year 2015-16;

And whereas by notification number 3134 (E) dated 17<sup>th</sup> October, 2013, the estimated cost was enhanced from Rs.853.90 lakhto Rs. 2434.12 lakh;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond eight years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years. However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961),- (a) hereby notifies the scheme or project “Mid-day Meal Project” which is being carried out by “Iskcon Food Relief Foundation, Hare Krishna Land, Juhu, Mumbai 400 049”, without any change in the approved cost of Rs. 2434.12 lakh, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial years 2016-17 i.e. 2016-17, 2017-18 and 2018-19;

(b) The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No. 43 /2016 / F.No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

**का. आ.1527 (अ).-** जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 12.07.2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 1649 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “सूरत मानव सेवा संघ, छनयादो, नया सिविल हॉस्पिटल परिसर, मजुरे गेट, सूरत-395001 गुजरात” द्वारा “मरीजों के लिए डायलिसिस केंद्र” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2010-11 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए कॉर्पस निधि के रूप में 10 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 30 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 27 दिसंबर, 2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 3864 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छः वर्षों से आगे बढ़ने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है। तथापि, धारा 35 क ग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (क) एतद्वारा “सूरत मानव सेवा संघ, छनयादो, नया सिविल हॉस्पिटल परिसर, मजुरे गेट, सूरत-395001 गुजरात” द्वारा चलाई जा रही “मरीजों के लिए डायलिसिस केंद्र” की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए कॉर्पस निधि के रूप में 10 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है;

(ख) धारा 35 क ग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।

[सं. 44/2016 /फा. सं. वी.27015/1/2016 एस ओ( एन. सी.)]

मन्मथ लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th April, 2016

**S.O.1527 (E).—** Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. No.1649(E) dated 12.07.2010, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 30 “Dialysis Centre for Patients” by “Surat Manav Seva Sangh, Chhanyado, New Civil Hospital Campus, Majura Gate, Surat 395001, Gujarat”, at the estimated cost of Rs.10 crore as a corpus fund, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2010-11 and which was further extended vide notification number S.O. 3864 (E) dated 27<sup>th</sup> December, 2013 for a period of three years ending with financial year 2015-16;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years. However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), - (a) hereby notifies the scheme or project “Dialysis Centre for Patients”, which is being carried out by “Surat Manav Seva Sangh, Chhanyado, New Civil



Hospital Campus, Majura Gate, Surat 395001, Gujarat”, without any change in the approved cost of Rs.10 crore as a corpus fund, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial years, 2016-17 i.e. 2016-17, 2017-18 and 2018-19;

(b) The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No. 44/2016 / F.No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

**का. आ.1528 (अ).-** जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 11.05.2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 1052 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “मद्रास एगमोर लॉयन्स ब्लड बैंक और रिसर्च फाउंडेशन, 130, मार्शल रोड, एगमोर, चैन्ने-600008” द्वारा “ब्लड बैंक, चिकित्सीय उपकरण और सुविधाओं की विस्तार परियोजना” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2010-11 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 5.04 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 12 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 27 दिसंबर, 2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 3865 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छः वर्षों से आगे बढ़ने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है। तथापि, धारा 35 क ग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (क) एतद्वारा “मद्रास एगमोर लॉयन्स ब्लड बैंक और रिसर्च फाउंडेशन, 130, मार्शल रोड, एगमोर, चैन्ने-600008” द्वारा चलाई जा रही “ब्लड बैंक, चिकित्सीय उपकरण और सुविधाओं की विस्तार परियोजना” की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए 5.04 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है;

(ख) धारा 35 क ग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।

[सं. 45/2016 /फा. सं. वी.27015/1/2016 एस ओ( एन. सी.)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2016

**S.O.1528 (E).—** Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.1052(E) dated 11.05.2010, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 12 “Blood Bank Medical Equipment and facilities expansion project” by “Madras Egmore Lions Blood Bank & Research Foundation, 130, Marshalls Road, Egmore, Chennai 600 008”, at the estimated cost of Rs.5.04 crore, as an eligible project

or scheme for a period of three years beginning with financial year 2010-11 and which was further extended vide notification number S.O. 3865 (E) dated 27<sup>th</sup> December, 2013 for a period of three years ending with financial year 2015-16;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years. However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), - (a) hereby notifies the scheme or project "Blood Bank Medical Equipment and facilities expansion project", which is being carried out by "Madras Egmore Lions Blood Bank & Research Foundation, 130, Marshalls Road, Egmore, Chennai 600 008", without any change in the approved cost of Rs.5.04 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial years, 2016-17 i.e. 2016-17, 2017-18 and 2018-19.

(b) The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No.45/2016 / F.No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

**का. आ.1529 (अ).-** जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 18.12.2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 3696 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "उदबम करनगल, सं० 460, एन.एस.के. नगर, अरुमबक्कम, चैन्ने, 600106, तमिलनाडु" द्वारा "मानसिक रूप से विकलांग मरीजों के लिए शांतिवनम पुनर्वास केंद्र-मदुरई" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2015-16 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 8.20 करोड़ रुपये की कॉर्पस निधि सहित 16 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 17 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से आगे बढ़ने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है। तथापि, धारा 35 क ग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (क) एतद्वारा "उदबम करनगल, सं. 460, एन.एस.के. नगर, अरुमबक्कम, चैन्ने, 600106, तमिलनाडु" द्वारा चलाई जा रही "मानसिक रूप से विकलांग मरीजों के लिए शांतिवनम पुनर्वास केंद्र-मदुरई" की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए 8.20 करोड़ रुपये की कॉर्पस निधि सहित 16 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है;

(ख) धारा 35 क ग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।

[सं. 46/2016 /फा. सं. वी.27015/1/2016 एस ओ( एन. सी.)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th April, 2016

**S.O.1529 (E).—** Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 3696(E) dated 18.12.2013 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 17, “Shanthivanam Rehabilitation Centre for Mentally disabled patients-Madurai” by “Udavum Karangal, No.460, N.S.K. Nagar, Arumbakkam, Chennai, 600106, Tamilnadu”, as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 16 crore including a corpus fund of Rs. 8.20 crore for a period of three years ending with financial year 2015-16;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years. However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (a) hereby notifies the scheme or project “Shanthivanam Rehabilitation Centre for Mentally disabled patients-Madurai”, which is being carried out by “Udavum Karangal, No.460, N.S.K. Nagar, Arumbakkam, Chennai, 600106, Tamilnadu”, as an eligible project or scheme for a further period of three years, without any change in the approved cost of Rs. 16 crore including a corpus fund of Rs. 8.20 crore commencing with the financial year 2016-17 i.e. 2016-17, 2017-18 and 2018-19;

(b). The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No. 46/2016 / F.No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

**का. आ.1530 (अ).-** जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 12.07.2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 1649 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “श्री पंचमहल अनुसूचित जाति एजुकेशन ट्रस्ट, अदादरा तालुका, कलोल जिला, पंचमहल, गुजरात” द्वारा “गूंगे और बहरे छात्रों के लिए स्कूल का संचालन और विस्तार” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 1.90 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 13 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 4 जून, 2015 की अधिसूचना सं. का. आ. 1480 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छः वर्षों से आगे बढ़ने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है। तथापि, धारा 35 क ग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (क) एतद्वारा “श्री पंचमहल अनुसूचित जाति एजुकेशन ट्रस्ट, अदादरा तालुका, कलोल जिला, पंचमहल, गुजरात” द्वारा चलाई जा रही “गूंगे और बहरे छात्रों के लिए स्कूल का संचालन और विस्तार” की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2016-17, 2017-18

और 2018-19 के लिए 1.90 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है;

(ख) धारा 35 क ग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।

[सं. 47/2016 /फा. सं. वी.27015/1/2016 एस ओ( एन. सी.)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2016

**S.O.1530 (E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1649(E) dated 12.07.2010 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 13, “Expansion & running the school for deaf & dumb students” by “Shree Panchmahal Anusuchit Jati Education Trust, Adadara Ta, Kalol District, Panchmahal, Gujarat.”, as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 1.90 crore for a period of three years ending with financial year 2012-13 and which was further extended vide notification number S.O. 1480 (E) dated 4<sup>th</sup> June, 2015 for a period of three years ending with financial year 2015-16;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 6 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years. However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (a) hereby notifies the scheme or project “Expansion & running the school for deaf & dumb students”, which is being carried out by “Shree Panchmahal Anusuchit Jati Education Trust, Adadara Ta, Kalol District, Panchmahal, Gujarat”, without any change in the approved cost of Rs. 1.90 crore for a further period of three years commencing with financial year 2016-17 i.e. 2016-17, 2017-18 and 2018-19;

(b) The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No. 47/2016 / F.No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

**का. आ.1531 (अ).**— जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 04.10.2012 की अधिसूचना सं. का. आ. 2366(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “बरसात अन्वेषण, रविन्द्र नगर, डाकखाना- नाउपारा, बरसात, उत्तर 24 परगना-700125” द्वारा “वर्तमान में निवेदिता अनाथालय एवं वृद्धाश्रम के क्रियाकलापों का विस्तार” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 50 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 282.13 लाख रुपए की अनुमोदित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 27 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है। तथापि,

धारा 35 कग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (क) एतद्वारा “बरसात अन्वेषण, रविन्द्र नगर, डाकखाना- नाउपारा, बरसात, उत्तर 24 परगना-700125” द्वारा चलाई जा रही “वर्तमान में निवेदिता अनाथालय एवं वृद्धाश्रम के क्रियाकलापों का विस्तार” की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए 50 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 282.13 लाख रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है;

(ख) धारा 35 कग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।

[सं. 48/2016 /फा. सं. वी -27015/1/2016 एस ओ( एन. सी)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2016

**S.O.1531 (E).—** Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2366(E) dated 4.10.2012 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 27, “Enhancement of the activities of present Nivedita Orphanage Home and Old age Home ‘Sankalp’” by “Barasat Anweshan, Rabindra Nagar, P.O. Noapara, Barasat, North 24 Parganas,– 700 125, West Bengal”, as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 282.13 lakh including corpus funds of Rs. 50 lakh for a period of three years ending with financial year 2014-15;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years. However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (a) hereby notifies the scheme or project “Enhancement of the activities of present Nivedita Orphanage Home and Old age Home ‘Sankalp’” which is being carried out by “Barasat Anweshan, Rabindra Nagar, P.O. Noapara, Barasat, North 24 Parganas,– 700 125, West Bengal”, as an eligible project or scheme for a further period of three years, without any change in the approved cost of Rs. 282.13 lakh including corpus funds of Rs. 50 lakh commencing with the financial year 2015-16 i.e. 2015-16, 2016-17 and 2017-18. As the financial year 2015-16 has already been lapsed, no certificate under section 35AC of the IT Act, 1961 would be issued for the financial year 2015-16;

(b). The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No. 48/2016 / F.No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

**का. आ.1532 (अ).-** जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 16.05.2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 1253(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “हरोआ अल- जामियातुल इस्लामिया दारुल उल्लूम कलिकापुर, डाकखाना सदरपुर बेहाला,

पीएस -हरोआ, जिला-नार्थ 24 परगना-743445 (पश्चिम बंगाल)" द्वारा "वर्तमान क्रियाकलापों का अनुरक्षण" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2015-16 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 17.00 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 04 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है। तथापि, धारा 35 कग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (क) एतद्वारा "हरोआ अल- जामियातुल इस्लामिया दारुल उल्लूम कलिकापुर, डाकखाना सदरपुर बेहाला, पीएस -हरोआ, जिला-नार्थ 24 परगना-743445 (पश्चिम बंगाल)" द्वारा चलाई जा रही "वर्तमान क्रियाकलापों का अनुरक्षण" की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए 17.00 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है;

(ख) धारा 35 कग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।

[सं. 49/2016 /फा. सं. वी -27015/1/2016 एस ओ( एन. सी)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2016

**S.O.1532 (E).—** Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1253(E) dated 16.5.2013 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 4, "Maintenance of present activities" by "Harora Al-Jamiatul Islamia Darul Uloom Kalikapur, P.O. Sadarpur Behala, P.S.-Harora, Dist-North 24 Parganas – 743445. (West Bengal)", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of 17.00 crore for a period of three years ending with financial year 2015-16;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years. However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (a) hereby notifies the scheme or project "Maintenance of present activities", which is being carried out by "Harora Al-Jamiatul Islamia Darul Uloom Kalikapur, P.O. Sadarpur Behala, P.S.-Harora, Dist-North 24 Parganas – 743445. (West Bengal)", as an eligible project or scheme for a further period of three years, without any change in the approved cost of 17.00 crore commencing with the financial year 2016-17 i.e. 2016-17, 2017-18 and 2018-19;

(b) The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No.49 /2016 / F.No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

**का. आ.1533 (अ).-** जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 24.01.2005 की अधिसूचना सं. का. आ. 81 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन, दूसरा तल, नाना चौक नगरपालिका स्कूल, फ्रेरे ब्रिज लो लेवल, ग्रांड रोड स्टेशन के नजदीक, मुंबई-400007" द्वारा "चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2004-05 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 4 पर अधिसूचित किया था; जिसे बाद में दिनांक 16.07.2007 की अधिसूचना सं. का. आ. 1159 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 21.07.2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 1792 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 17.10.2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 3164(अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 17.10.2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 3164(अ) के द्वारा अनुमोदित लागत को 2.66 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4.66 करोड़ रुपये कर दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के बारह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है। तथापि, धारा 35 क ग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (क) एतद्वारा "चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन, दूसरा तल, नाना चौक नगरपालिका स्कूल, फ्रेरे ब्रिज लो लेवल, ग्रांड रोड स्टेशन के नजदीक, मुंबई-400007" द्वारा चलाई जा रही "चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन" की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए 4.66 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है;

(ख) धारा 35 क ग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।

[सं. 50/2016 /फा. सं. वी -27015/1/2016 एस ओ( एन. सी)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th April, 2016

**S.O.1533 (E).—** Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.81(E) dated the 24<sup>th</sup> January, 2005, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 4, for 'Childline India Foundation' by 'Childline India Foundation, 2nd Floor, Nanachowk Municipal School, Frere Bridge Low Level, Near Grant Road Station, Mumbai-400 007', as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2004-2005; which was extended further vide notification number 1159(E) dated 16<sup>th</sup> July, 2007 for a period of three years beginning with financial year 2007-08, which was vide Notification number S.O. 1792 (E) dated 21<sup>st</sup> July, 2010 further extended for a period of three years ending with financial year 2012-2013 and which was vide Notification number S.O. 3164(E) dated 17.10.2013 further extended for a period of three years ending with financial year 2015-2016.

And whereas by notification number 3164 (E) dated 17<sup>th</sup> October, 2013, the estimated cost was enhanced from Rs.2.66 crore to Rs. 4.66 crore;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond twelve years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years. However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), - (a) hereby notifies the scheme or project for Childline India Foundation, which is being carried out by "Childline India Foundation, 2nd Floor, Nanachowk Municipal School, Frere Bridge Low Level, Near Grant Road Station, Mumbai-400 007", as an eligible project or scheme, for a further period of three years without any change in the approved cost of Rs. 4.66 crore beginning with financial year i.e. 2016-17, 2017-18 and 2018-19;

(b). The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No.50 /2016 / F.No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

**का. आ.1534 (अ).-** जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 11.11.2005 की अधिसूचना सं. का. आ. 1586 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "मोहन फाउंडेशन ए- 81, अन्ना नगर, चेन्नई-600102" द्वारा "मल्टी और्गन हारवेस्टिंग एंड शेयरिंग नेटवर्क इन इंडिया" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2007-08 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 1.97 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 4 पर अधिसूचित किया था; जिसे बाद में दिनांक 06.10.2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 2036 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 27.04.2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 883 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 31.07.2014 की अधिसूचना सं. का. आ. 1944(अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि परियोजना लागत 1.97 करोड़ रुपये से बढ़कर 5.00 करोड़ रुपये होने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना लागत को 1.97 करोड़ रुपये से 5.00 करोड़ रुपये करने की सिफारिश की है। तथापि, धारा 35 क ग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा "मोहन फाउंडेशन ए- 81, अन्ना नगर, चेन्नई-600102" द्वारा चलाई जा रही "मल्टी और्गन हारवेस्टिंग एंड शेयरिंग नेटवर्क इन इंडिया" की परियोजना अथवा स्कीम को एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है; (क) दिनांक 11-11-2005 की अधिसूचना सं. का. आ. 1586 (अ) को निम्नलिखित आशय से संशोधित करती है, नामतः



उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 04 के सामने तालिका में आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली लागत की अधिकतम राशि से संबंधित कॉलम (4) में “1.97 करोड़ रुपये” से संबंधित अक्षरों, अंको और शब्दों को “5.00 करोड़ रुपये” से संबंधित अक्षरों, अंको और शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) धारा 35 क ग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।

[सं. 51/2016 /फा. सं. वी -27015/1/2016 एस ओ( एन. सी)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2016

**S.O.1534 (E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.1586(E) dated 11.11.2005 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 4, “Multi Organ Harvesting and Sharing Network in India” by “Mohan Foundation A-81, Anna Nagar, Chennai - 600 102”, as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.1.97 crore, for a period of three years ending with financial year 2007-08, which was further extended vide notification number S.O.2036(E) dated 06.10.2009 for a period of three years ending with financial year 2010-11, and which was further extended vide notification number S.O.883(E) dated 27.04.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14 and which was further extended vide notification number S.O.1944(E) dated 31.7.2014 for a period of three years ending with financial year 2016-17;

And whereas the project cost is likely to enhance from Rs.1.97 crore to Rs. 5.00 crore;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for amending the project cost from Rs. 1.97 crore to Rs. 5.00 crore. However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project “Multi Organ Harvesting and Sharing Network in India”, which is being carried out by “Mohan Foundation A-81, Anna Nagar, Chennai - 600102”, (a) further amends the said notification number S.O. 1586(E) dated 11.11.2005, to the following effect, namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 4, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section of 35AC of Income Tax Act, 1961 for the letters, figures and word “Rs.1.97 crore” the letters, figures and word “Rs. 5.00 crore” shall be substituted.

(b). The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No.51 /2016 / F.No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

**का. आ.1535 (अ).**— जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 18.03.2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 614 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “भारती विद्यापीठ, भारती विद्यापीठ भवन, एलबीएस मार्ग, पुणे-411030” द्वारा “मेडिकल हॉस्पिटल एवं अनुसंधान केन्द्र का रख-रखाव और संचालन” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 26.01 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 35 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं 33 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 17.10.2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 3156 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छः वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है। तथापि, धारा 35 कग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (क) एतद्वारा “भारती विद्यापीठ, भारती विद्यापीठ भवन, एलबीएस मार्ग, पुणे -411030” द्वारा चलाई जा रही “मेडिकल हॉस्पिटल एवं अनुसंधान केन्द्र का रख-रखाव और संचालन” की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए 26.01 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 35 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है;

(ख) धारा 35 कग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।

[सं. 52/2016 /फा. सं. वी -27015/1/2016 एस ओ( एन. सी)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2016

**S.O.1535 (E).—** Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 614 (E) dated 18<sup>th</sup> March, 2010 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 33 “Running and Maintenance of Medical Hospital and Research Centre” by “Bharati Vidyapeeth, Bharati Vidyapeeth Bhavan, L.B.S Marg, Pune 411030”, as an eligible project at the estimated cost of Rs.35 crore including a corpus fund of Rs.26.01 crore, for a period of three years ending with financial year 2012-13 and which was vide Notification number S.O. 3156(E) dated 17.10.2013 further extended for a period of three years ending with financial year 2015-2016.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 6 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years. However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (a) hereby notifies the scheme or project “Running and Maintenance of Medical Hospital and Research Centre” which is being carried out by “Bharati Vidyapeeth, Bharati Vidyapeeth Bhavan, L.B.S Marg, Pune 411030”, without any change in the approved cost of Rs.35 crore including a corpus fund of Rs.26.01 crore, as an eligible project or scheme, for a further period of three years commencing with financial year 2016-17, 2017-18 and 2018-19;

(b). The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No.52 /2016 / F.No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

**का. आ.1536 (अ).-** जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 16.05.2016 की अधिसूचना सं. का. आ. 1253 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "सोशल एक्शन फॉर मैन पावर क्रिएशन (सम्पर्क), 9, वाराद अपार्टमेंट, प्लॉट न.-292, क्रम सं. 37-45, यशवंत नगर, तालेगांव, दभाडे स्टेशन, पुणे-410507" द्वारा "(1) सम्पर्क परियोजना क्षेत्र के अनाथ, निर्धन, जरूरतमंद एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए खेल-कूद प्रशिक्षण केन्द्र का विकास एवं संवर्धन (2) चारदिवारी सहित भाजे बाल ग्राम का मरम्मत एवं नवीनीकरण, (3) प्रथम तल का निर्माण, (4) गरीब एवं जरूरतमंद बच्चों के लिए सहायक परामर्श केन्द्र, (5) महाराष्ट्र राज्य के संस्थानों के कर्मचारियों के लिए 1200 आवास क्षेत्र की क्षमता का विस्तार करना, (6) 650 अनाथ एवं जरूरतमंद बच्चों के देखभाल हेतु प्रायोजन सहायता, (7) संस्थान को आत्म निर्भर बनाए रखने के लिए कार्पस निधि जुटाना, (8) ग्रामीण, जरूरतमंद, निर्धन एवं निराश्रित 950 बच्चों के लिए शैक्षणिक प्रायोजन" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2015-16 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 13.19 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 07 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है। तथापि, धारा 35 क ग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (क) एतद्वारा "सोशल एक्शन फॉर मैन पावर क्रिएशन (सम्पर्क), 9, वाराद अपार्टमेंट, प्लॉट न.-292, क्रम सं. 37-45, यशवंत नगर, तालेगांव, दभाडे स्टेशन, पुणे-410507" द्वारा चलाई जा रही "(1) सम्पर्क परियोजना क्षेत्र के अनाथ, निर्धन, जरूरतमंद एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए खेल-कूद प्रशिक्षण केन्द्र का विकास एवं संवर्धन (2) चारदिवारी सहित भाजे बाल ग्राम की मरम्मत एवं नवीनीकरण, (3) प्रथम तल का निर्माण, (4) गरीब एवं जरूरतमंद बच्चों के लिए सहायक परामर्श केन्द्र, (5) महाराष्ट्र राज्य के संस्थानों के कर्मचारियों के लिए 1200 आवास क्षेत्र की क्षमता का विस्तार करना, (6) 650 अनाथ एवं जरूरतमंद बच्चों के देखभाल हेतु प्रायोजन सहायता, (7) संस्थान को आत्म निर्भर बनाए रखने के लिए कार्पस निधि जुटाना, (8) ग्रामीण, जरूरतमंद, निर्धन एवं निराश्रित 950 बच्चों के लिए शैक्षणिक प्रायोजन" की परियोजना अथवा स्कीम को 13.19 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए अधिसूचित करती है;

(ख) धारा 35 क ग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।

[सं. 53/2016 /फा. सं. वी -27015/1/2016 एस ओ( एन. सी)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th April, 2016

**S.O.1536 (E).—**Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1253(E) dated 16.05.2013 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 7, "(1) Promotion and development of sports training centre for orphan, poor, needy & tribal children of SAMPARC project area. (2) Repairs

& renovations of Bhaje Balgram including fencing. (3) Construction of first floor (4) Supporting counseling centre for poor & needy children (5) Enhancing the capacity of staff 1200 residential institutions staff of Maharashtra state (6) Sponsorship assistance for the care of 650 orphan & needy children (7) Raising corpus fund for making the organization self-sustain (8) Educational sponsorship for the poor needy rural and destitute 950 children” by “Social Action for Manpower Creation (SAMPARC), 9, Varad Apartment, Plot No. 292, S.No. 37-45, Yashwant Nagar, Talegaon Dabhade Station, Pune – 410 507”, as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 13.19 crore for a period of three years ending with financial year 2015-16;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years. However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (a) hereby notifies the scheme or project “(1)

Promotion and development of sports training centre for orphan, poor, needy & tribal children of SAMPARC project area. (2) Repairs & renovations of Bhaje Balgram including fencing. (3) Construction of first floor (4) Supporting counseling centre for poor & needy children (5) Enhancing the capacity of staff 1200 residential institutions staff of Maharashtra state (6) Sponsorship assistance for the care of 650 orphan & needy children (7) Raising corpus fund for making the organization self-sustain (8) Educational sponsorship for the poor needy rural and destitute 950 children”, which is being carried out by “Social Action for Manpower Creation (SAMPARC), 9, Varad Apartment, Plot No. 292, S.No. 37-45, Yashwant Nagar, Talegaon Dabhade Station, Pune – 410 507”, as an eligible project or scheme for a further period of three years, without any change in the approved cost of Rs. 13.19 crore commencing with the financial year 2016-17 i.e. 2016-17, 2017-18 and 2018-19;

(b). The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No.53/2016 / F.No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

**का. आ.1537(अ).**-जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 18.10.2001 की अधिसूचना सं. का. आ. 1045 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “सेंस इन्टरनेशनल (इंडिया), 405 फेबरेट रेजिडेन्सी, सेन्ट जेवीअर्स लोयोला स्कूल के सामने, मेमनगर, अहमदाबाद -380015” द्वारा “सम्पूर्ण भारत में बहरे नेत्रहीन के लिए व्यापक पुनर्वास सेवाओं ” की परियोजना को निश्चरित वर्ष 2002-03 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 05 पर अधिसूचित किया था; जिसे बाद में दिनांक 23.03.2005 की अधिसूचना सं. का. आ. 397 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-05 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 16.07.2007 की अधिसूचना सं. का. आ. 1147 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 को प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 14.05.2012 की अधिसूचना सं. का. आ. 1091 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 17.10.2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 3150 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 17.10.2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 3150 (अ) के द्वारा परियोजना लागत को 2.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10.00 करोड़ रुपये कर दिया गया था।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के पन्द्रह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-

नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है। तथापि, धारा 35 कग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (क) एतद्वारा “सेंस इन्टरनेशनल (इंडिया), 405 फेवरेट रजिडेन्सी, सेंट जेव्रीअर्स लोयोला स्कूल के सामने, मेमनगर, अहमदाबाद -380015” द्वारा चलाई जा रही “सम्पूर्ण भारत में बहरे नेत्रहीन के लिए व्यापक पुनर्वास सेवाओं ” की परियोजना अथवा स्कीम को 10.00 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए अधिसूचित करती है;

(ख) धारा 35 कग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।

[सं. 54/2016 /फा. सं. वी -27015/1/2016 एस ओ( एन. सी)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2016

**S.O.1537(E).**—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.1045(E) dated the 18<sup>th</sup> October, 2001, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 5, “for Comprehensive rehabilitation services for the deaf blind all over India” by “Sense International (India), 405, Favorite Residency, Opposite Saint Xavier’s Loyola School, Memnagar, Ahmedabad-380015”, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment years 2002-2003, which was extended further vide notification number S.O.397(E) dated the 23<sup>rd</sup> March, 2005 for a period of three years beginning with financial year 2004-2005, which was extended further vide notification number S.O. 1147(E) dated 16<sup>th</sup> July, 2007 for a period of three years beginning with the financial year 2007-08, which was extended further vide notification number S.O. No.1091 (E) dated 14<sup>th</sup> May, 2012 for a period of three years ending with financial year 2012-13 and which was extended further vide notification number S.O. No.3150 (E) dated 17<sup>th</sup> October, 2013 for a period of three years ending with financial year 2015-16;

And whereas by notification number 3150 (E) dated 17<sup>th</sup> October, 2013, the estimated cost was enhanced from Rs.2.00 crore to Rs. 10.00 crore;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond fifteen years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years. However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (a) hereby notifies the scheme or project for “Comprehensive rehabilitation services for the deaf blind all over India”, which is being carried out by “Sense International (India), 405, Favorite Residency, Opposite Saint Xavier’s Loyola School, Memnagar, Ahmedabad-380015”, as an eligible project or scheme for a further period of three years without any change in the approved cost of Rs. 10.00 crore commencing with the financial year 2016-17 i.e. 2016-17, 2017-18 and 2018-19;

(b). The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No. 54 /2016 / F.No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

**का. आ.1538 (अ).-** जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 20.09.2001 की अधिसूचना सं. का. आ. 901 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “अमर ज्योति धर्मार्थ न्यास, एन-192, ग्रेटर कैलाश-1 नई दिल्ली-110048” द्वारा “एकीकृत शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, चिकित्सा देखभाल और रोजगार अवसरों के माध्यम से अपंग व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु भवन का निर्माण, पुस्तकालय किताबों की खरीद, कार्यालय एवं खेल-कूद उपस्कर, मोबाईल सहायक-सामग्री और उपकरण, अध्ययन सामग्रियां साज-सज्जा एवं गतिविधियों का संचालन ” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2003-04 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 225.84 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 03 पर अधिसूचित किया था जिसे बाद में दिनांक 23.03.2005 की अधिसूचना सं. का. आ. 389 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 23.12.2000 की अधिसूचना सं. का. आ. 1800 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 11.10.2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 2525 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 17.10.2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 3121 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 27.12.2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 2890 (अ) के द्वारा परियोजना लागत को 225.84 लाख रुपये से बढ़ाकर 1550.00 लाख रुपये कर दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के पन्द्रह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है। तथापि, धारा 35 क ग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (क) एतद्वारा “अमर ज्योति धर्मार्थ न्यास, एन-192, ग्रेटर कैलाश-1 नई दिल्ली-110048” द्वारा चलाई जा रही “एकीकृत शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, चिकित्सा देखभाल और रोजगार अवसरों के माध्यम से अपंग व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु भवन का निर्माण, पुस्तकालय किताबों की खरीद, कार्यालय एवं खेल-कूद उपस्कर, मोबाईल सहायक-सामग्री और उपकरण, अध्ययन सामग्रियां साज-सज्जा एवं गतिविधियों का संचालन ” की परियोजना अथवा स्कीम को 1550.00 लाख रुपये की अनुमोदित लागत में परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए अधिसूचित करती है;

(ख) धारा 35 क ग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।

[सं. 55/2016 /फा. सं. वी -27015/1/2016 एस ओ( एन. सी)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th April, 2016

**S.O.1538 (E).—**Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 901(E) dated 20<sup>th</sup> September, 2001 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of

the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 3 “Construction of Building, Purchase of Library Books, Office and Sports equipment, Mobile aids and appliances, learning materials, furnishing and running of activities for rehabilitation of persons with disability through integrated education, vocational training, medical care and employment opportunities” by “Amar Jyoti Charitable Trust, N-192, Greater Kailash-I, New Delhi – 110048”, as an eligible project at the estimated cost of Rs 225.84 Lakh for a period of three years ending with financial year 2003-04; which was further extended vide notification number S.O. 389(E) dated 23<sup>rd</sup> March, 2005 for a period of three years ending with financial year 2006-07, which was further extended vide notification number S.O. 1800(E) dated 23<sup>rd</sup> October, 2007 for a period of three years ending with financial year 2009-10, which was further extended vide notification number S.O.2525(E) dated 11<sup>th</sup> October, 2010 for a period of three years ending with financial year 2012-13 and which was further extended vide notification number S.O.3121(E) dated 17<sup>th</sup> October, 2013 for a period of three years ending with financial year 2015-16;

And whereas by notification number S.O. 2890(E) dated 27<sup>th</sup> December, 2011, the project cost was enhanced from Rs.225.84 lakh to Rs.1550.00 lakh;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 15 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years. However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (a) hereby notifies the scheme or project “Construction of Building, Purchase of Library Books, Office and Sports equipment, Mobile aids and appliances, learning materials, furnishing and running of activities for rehabilitation of persons with disability through integrated education, vocational training, medical care and employment opportunities” which is being carried out by “Amar Jyoti Charitable Trust, N-192, Greater Kailash-I, New Delhi – 110048”, without any change in the approved cost of Rs.1550.00 lakh, as an eligible project or scheme, for a further period of three years commencing with financial year 2016-17 i.e. 2016-17, 2017-18 and 2018-19;

(b). The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No. 55 /2016 / F.No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

**का. आ.1539 (अ).**- जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 28.09.2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 2349 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, सेंट्रल ग्रीन, के.सी रोड, एनआईटी, फरीदाबाद-121001” द्वारा “नेत्रहीनों के कल्याण हेतु परियोजना चलाने” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 300 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 01 पर अधिसूचित किया था और जिसे बाद में दिनांक 17.10.2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 3186 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है। तथापि, धारा 35 क ग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (क) एतद्वारा “नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, सेंट्रल ग्रीन, के.सी रोड, एनआईटी, फरीदाबाद-121001” द्वारा चलाई जा रही “नेत्रहीनों के कल्याण हेतु परियोजना चलाने” की परियोजना अथवा स्कीम को 300 लाख रुपये की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए अधिसूचित करती है;

(ख) धारा 35 क ग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।

[सं. 56/2016 /फा. सं. वी -27015/1/2016 एस ओ( एन. सी)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2016

**S.O.1539 (E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. No. 2349 (E) dated 28<sup>th</sup> September, 2010, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 1, “Running projects for the welfare of visually impaired” by “National Association for the Blind, Central Green, K.C Road, NIT, Faridabad-121001”, as an eligible project or scheme for a period of three years at the estimated cost of Rs.300 lakh, ending with financial year 2012-13 and which was further extended vide notification number S.O.3186(E) dated 17<sup>th</sup> October, 2013 for a period of three years ending with financial year 2015-16;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 6 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years. However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (a) hereby specifies the scheme or project “Running projects for the welfare of visually impaired”, which is being carried out by “National Association for the Blind, Central Green, K.C Road, NIT, Faridabad-121001”, without any change in the approved cost of Rs.300 lakh, as an eligible project or scheme, for a further period of three years commencing with the financial year 2016-17 i.e. 2016-17, 2017-18 and 2018-19;

(b). The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No. 56 /2016 / F.No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

**का. आ.1540 (अ).**- जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 17.06.2008 की अधिसूचना सं. का. आ. 1462 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “इस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन, हरे कृष्णा लैंड, जुहू, मुम्बई-400049” द्वारा “उत्तर प्रदेश के लिए मध्याह्न भोजन” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2008-09 से प्रारंभ होने वाली दो वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 10 पर अधिसूचित किया था और जिसे बाद में दिनांक 21.07.2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 1787 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद दिनांक 27.12.2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 3868 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;



और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के आठ वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है। तथापि, धारा 35 कग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (क) एतद्वारा “इस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन, हरे कृष्णा लैंड, जुहु, मुम्बई-400049” द्वारा चलाई जा रही “उत्तर प्रदेश के लिए मध्याह्न भोजन” की परियोजना अथवा स्कीम को 712.65 लाख रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए अधिसूचित करती है;

(ख) धारा 35 कग के तहत छूट कंपनी अधिनियम और कंपनियां (सीएसआर) नियमावली, 2014 की धारा 135 की अनुसूची VII के अंतर्गत प्राप्त निधियों पर लागू नहीं होगी।

[सं. 57/2016 /फा. सं. वी -27015/1/2016 एस ओ( एन. सी)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2016

**S.O.1540 (E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1462(E) dated 17<sup>th</sup> June, 2008, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 10, “Mid day meal project for Uttar Pradesh” by “Iskcon Food Relief Foundation, Hare Krishna Land, Juhu, Mumbai 400 049”, as an eligible project or scheme for a period of two years beginning with financial year 2008-09; and which was further extended vide notification number S.O. 1787(E) dated 21.07.2010 for a period of three years ending with financial year 2012-13 and which was further extended vide notification number S.O. 3868(E) dated 27.12.2013 for a period of three years ending with financial year 2015-16;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond eight years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years. However, the exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (a) hereby notifies the scheme or project “Mid day meal project for Uttar Pradesh”, is being carried out by “Iskcon Food Relief Foundation, Hare Krishna Land, Juhu, Mumbai 400 049”, without any change in the approved cost of Rs. 712.65 lakh, as an eligible project or scheme for a further period of three financial years commencing with the financial year 2016-17 i.e. 2016-17, 2017-18 and 2018-19;

(b) The exemption u/s 35AC will not apply to the funds received under Schedule VII of the Section 135 of the Companies Act and Companies (CSR) Rules 2014.

[No.57 /2016 / F.No.V. 27015/1/2016-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

**का. आ.1541 (अ).**-भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड-(ii) में 15.03.2016 को प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना का. आ. 1103 (अ) दिनांक 15.03.2016 में क्रम सं. 40 पर स्तम्भ सं. 3 में “(i)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (ii) पुज्य एल.एम.वोरा कन्या उच्च विद्यालय (iii) पुज्य एल.एम.वोरा कला और वाणिज्य महाविद्यालय, सायला (iv) नेत्र चिकित्सालय (v) प्रेम नि परब. 2565.25 लाख रुपये" को " (i) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 323.00 लाख रुपये (ii) पुज्य एल.एम.वोरा कन्या उच्च विद्यालय, 270.23 लाख रुपये (iii) पुज्य एल.एम.वोरा कला और वाणिज्य महाविद्यालय, सायला, 84.93 लाख रुपये (iv) नेत्र चिकित्सालय, 297.85 लाख रुपये (v) प्रेम नि परब. 115.00 लाख रुपये (vi) विस्तार कार्यक्रम (राज मंदिर), 1474.24 लाख रुपये" पढ़ा जाए।

[सं. 58/2016 /फा. सं. वी -27015/1/2016 एस ओ( एन. सी)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

### CORRIGENDUM

New Delhi, the 26th April, 2016

**S.O.1541 (E).**— In the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1103(E) dated 15th March, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated 15th March, 2016 at Serial No. 40 Column No. 3 "(i) Community Health Center (ii) Pujya L.M. Vora Girls High School (iii) Pujya L.M. Vora College of Arts & Commerce, Sayla (iv) Eye Hospital (v) Prem Ni Parab. Rs. 2565.25 lakh." may be read as "(i) Community Health Center, Rs. 323.00 lakh (ii) Pujya L.M. Vora Girls High School, Rs. 270.23 lakh (iii) Pujya L.M. Vora College of Arts & Commerce, Sayla, Rs. 84.93 lakh (iv) Eye Hospital, Rs. 297.85 (v) Prem Ni Parab, Rs. 115.00 lakh (vi) Expansion program (Raj Mandir), Rs. 1474.24 lakh".

[No.58 /2016/F.No.27015/1/2016-SO(NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)